● वर्ष-6
● अंक-102
रायपुर, मंगलवार
24 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

|| संगछध्वम् संवदध्वम् ||

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6›› घर की सब्जी को दें शाहू ट्विस्ट

एशिया पावर इंडेक्स 2026: दूसरे सबसे प्रभावी नेता बने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी



नई दिल्ली। वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के मोर्चे पर भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने एशिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश और एक मेजर पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हो गया है, जिससे वर्ष 2018 के बाद से चीन के साथ इसका फासला सबसे निचले स्तर पर पहुंच है। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद पूरे एशिया का दूसरा सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता माना है। सूचकांक के अनुसार, भारत ने इस वर्ष अपनी महाशक्ति की स्थिति को मजबूत करते हुए पूरे एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है। भारत के रक्षा नेटवर्क में 2.1 अंकों की ठोस बढ़त दर्ज की गई है। दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान देशों) के साथ भारत की बढ़ती क्षेत्रीय रक्षा साझेदारी और ब्रह्मोस मिसाइल की सफल बिक्री ने देश के सुरक्षा प्रभाव को नई ऊंचाई दी है।

गंगा जल संधि पर नरम पड़ी तारिक सरकार

बांग्लादेश ने नए समझौते की मांग छोड़ी, निकलेगा रास्ता



ढ़ाका। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने भारत के साथ तीन दशक पुरानी गंगा जल बंटवारा संधि पर नरमी के संकेत दिए हैं। अब तक बांग्लादेश नए समझौते की मांग कर रहा था। इस पर नरम पड़ते हुए ढाका ने दिल्ली से दिसंबर में संधि समाप्त होने से पहले इसके नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की अपील की है। दोनों पक्ष के अधिकारी फिलहाल 1996 में हुई इस संधि के खत्म होने से पहले नवीकरण की कोशिश में लगे हैं।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग के हेड शरद चंद्र और बांग्लादेश की छह सदस्यीय टीम को अनवर कादिर लीड कर रहे हैं। भारत का मानना ?? है कि गंगा संधि सहित पानी से जुड़े सभी सीमा-पार नदी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सिर्फ संयुक्त नदी आयोग ही स्थापित तंत्र है। वहीं ढाका एक नया समझौता चाहता है, जिसमें यह गारंटी हो कि सूखे के मौसम में उसे मिलने वाला पानी सुरक्षित रहे। इसके लिए नई दिल्ली एक तकनीकी टीम का गठन करे। दोनों पक्षों में इस पर काफी समय से बात चल रही है। गंगा संधि पर बांग्लादेश की 10 सदस्यीय तकनीकी समिति के प्रमुख और प्रधानमंत्री के सलाहकार राशद तितुमीर ने रविवार को कहा, हमने संधि से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उम्मीद है कि भारत अंतरराष्ट्रीय नदी गंगा के पानी के समान और निष्पक्ष बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। ढाका में संधि कार्यान्वयन पर बनी बांग्लादेश-भारत संयुक्त समिति की बैठक के बाद राशद तितुमीर ने कहा है कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि संधि की मौजूदा अवधि खत्म होने से पहले भारत कदम उठाएगा ताकि औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो। दोनों पक्षों ने संधि के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। संधि के नवीनीकरण या अंतरिम विस्तार और इसकी शर्तों के बारे में फैसला दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व लेगा। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी ने हाल ही में राजनयिक माध्यमों से अपने भारतीय समकक्ष को पत्र भेजा है, जिसमें संधि पर बातचीत जल्द शुरू करने का आग्रह किया है।

गंगा जल संधि मुद्दा क्या है?

- बांग्लादेश और भारत अहम पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच 54 साझा नदिया हैं, जो एक से दूसरी ओर जाती हैं।
- दोनों देशों में केवल गंगा ही ऐसी नदी है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच जल-बंटवारे का द्विपक्षीय समझौता है।
- गंगा जल बंटवारे का मुद्दा 1980 के दशक की शुरुआत से दोनों देशों के बीच बातचीत का विषय बन गया था।
- गंगा जल संधि 12 दिसम्बर 1996 को हुई थी। इस पर एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे।
- संधि के तहत जनवरी से मई तक नदी का बहाव 70000 क्यूसेक से कम होने पर दोनों देशों को पानी मिलता है।
- बहाव 70000 से 75000 क्यूसेक होने पर बांग्लादेश को 35000 क्यूसेक पानी दिए जाने का प्रावधान है।
- भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में अनिश्चितताओं का असर गंगा जल संधि के शांतिपूर्ण नवीनीकृत पर पड़ा है।

अमेरिका की हिरासत में 1389 भारतीय बच्चे

टेक्सास में छिपे लड़के के भारत डिपोर्ट हो चुके पिता ने साझा किया दर्द

नई दिल्ली, (ए)। गैरकानूनी घुसपैठ के खिलाफ अमेरिका इस समय बेहद सख्त है। इस बीच भारत से अमेरिका पहुंचे बच्चों को लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अमेरिकी वित्त वर्ष 2023 (FY23) से लेकर अब तक कुल 1,389 ऐसे भारतीय बच्चों को हिरासत में लिया गया है, जो वहां अकेले थे। इन बच्चों को अभी तक वापस उनके देश नहीं भेजा गया है। प्रवासियों के खिलाफ इस सख्त अभियान की वजह से अमेरिका में अकेले पाए जाने वाले भारतीय बच्चों की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023 में अमेरिका से 730 भारतीय बच्चे पकड़े गए थे। वही, वित्त वर्ष 2024 में 517, वित्त वर्ष 2025 में 91, वित्त वर्ष 2026 में 51, और अमेरिकी वित्त वर्ष 2027 के पहले महीने यानी अक्टूबर 2026 में 2 बच्चे हिरासत में लिए गए। डेटा US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (SCBP) से लिया गया है। यह गिरावट अलग-अलग देशों के उन बच्चों के मामले में भी दिख रही है, जो बिना किसी अभिभावक के यात्रा कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने एफवाय24 में 1.1 लाख, एफवाय25 में 29,584 और एफवाय26 में 9,190 ऐसे बच्चों का डेटा रिकॉर्ड किया, जो बिना किसी अभिभावक के थे।



ईरान पर हमले से फिर भड़क उठेगी जंग आईडीएफ की नेतन्याहू को चेतावनी

यरूशलम। इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर हमले की स्थिति में सामने आने वाले नतीजे से रूबरू कराया है। चेतावनी दी है कि ईरान पर हमले से एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है। टेलीविजन नेटवर्क चैनल 12 की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि, पिछले हफ्ते नेतन्याहू और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के बीच एक बंद कमरे में हुई बैठक में इसके नतीजे पर बात किया। कथित तौर पर इस समय ईरान के खिलाफ अपने सैन्य विकल्पों पर इजरायल गंभीरता से विचार कर रहा है।



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इनका उन्मूलन केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

बाहुबली बनने की कोशिश मत कीजिए: बिहार के जज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक न्यायिक अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते समय बाहुबली बनने की कोशिश न करें। मामला एक आईपीएस अधिकारी और रोहतास के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए दोषी ठहराने और एक रुपये का जुर्माना लगाने से जुड़ा है। शीर्ष अदालत ने जज के कानून की समझ पर सवाल उठाए और उनके रवैये को बेहद आक्रामक बताया। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारी को अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की



सीमा समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भेजने की बात भी कही। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बिहार के न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एसपी को एक रुपये का जुर्माना लगाने वाले उनके फैसले पर रोक लगा दी गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जज की कानून को समझने की क्षमता हैरान करने वाली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत के सामने ही किसी व्यक्ति का थप्पड़ मारना, गाली देना या अदालत के निर्देश के बावजूद वहां से नहीं हटना अलग तरह का अपराध है। लेकिन अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं करना अपने आप में अदालत के सामने किया गया अपराध नहीं माना जा सकता। पीठ ने जज के फैसले और कार्रवाई के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने पूछा कि क्या जज अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जिलाधिकारी और एसपी को अदालत में बुला सकते थे और उनके पेश नहीं होने को अदालत के सामने किया गया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

रूस से 1800 किमी दूर लीबिया तट पर रूसी युद्धपोत को उड़ाकर यूक्रेन ने रचा इतिहास

मॉस्को। लीबिया के तट पर रूसी युद्धपोत को उड़ाने की घटना के बाद दुनियाभर में यूक्रेनी नौसेना की ड्रोन बोट ताकत की तारीफ हो रही है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह अपने आप में असाधारण घटना है। वह भी तब जब यूक्रेनी नौसेना बहुत छोटी है। इस घटना की तुलना द्वह्रस्श्वद्वद्यड्डह्ल से हो रही है जब साल 1967 में एक शक्तिशाली इजरायली ड्रेस्ट्रायर को मिस्र की कोमार श्रेणी की मिसाइल बोट ने साल 1967 में भूमध्य सागर में उड़ा दिया था। इस दौरान मिस्र की बोट ने सोवियत संघ की क्क-15 टेरमिट एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 47 इजरायली मारे गए थे।



ट्रंप ने एनवीडिया में हुआंग की वापसी का फिर किया समर्थन



वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी का खुलकर समर्थन किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनवीडिया का निदेशक मंडल जेनसन हुआंग को फिर से नियुक्त करेगा। उन्होंने इसे कंपनी और अमेरिका के लिए सबसे अच्छी बात बताया। राष्ट्रपति का यह समर्थन एक बड़े विवाद के बीच आया है। एक अमेरिकी समाचार पत्र ने रिपोर्ट दी थी कि एलिस हुआंग नामक एक कथित चीनी जासूस का चीन की शीर्ष जासूसी एजेंसी के एक अधिकारी से संपर्क था। यह संपर्क एक साल से अधिक समय तक बना रहा। इसी दौरान वह जेनसन हुआंग के साथ गुप्त संबंध में थी। रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के कई जानकार लोगों का हवाला दिया। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि एलिस हुआंग 2025 के वसंत से इस साल के पतझड़ तक चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के संपर्क में थी।

दिल्ली में थाने के अंदर खूनखराबा नौ पुलिसकर्मियों पर हमला

नई दिल्ली। दिल्ली के जामा मस्जिद थाना में सोमवार दोपहर करीब 2.30 बजे एक बड़ी घटना हुई। पारिवारिक विवाद की शिकायत पर थाने बुलाए गए नबील नामक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नौ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। नबील को उसकी मां और बहन से जुड़े एक पारिवारिक विवाद के मामले में थाने बुलाया गया था। उसने अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को गर्दन और चेहरे पर चोटें आईं। उन्हें तुरंत संजीवनी अस्पताल ले जाया गया। बाद में बेहतर उपचार के लिए सर गंगा राम अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमले के बाद आरोपी नबील थाना से भाग निकला। भागने में मदद के लिए उसने रास्ते में एक दोपहिया वाहन भी लूट लिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की एक टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया।

ऑपरेशंस यूनिट की टीम ने आरोपी नबील को चितली कबर इलाके में ट्रैक किया। जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। नबील ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस स्थिति में पुलिस टीम को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी।

गोधरा कांड के दोषी को राहत, 18 साल से बंद कैदी की उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अग्निकांड मामले के दोषी इरफान सिराज पाडा की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने गौर किया कि पाडा 18 साल से अधिक समय से जेल में है और वह कई बीमारियों से जूझ रहा है। पीठ ने कहा, मुख्य रूप से यह अर्जी चिकित्सीय आधार पर दायर की गई है। राज्य के वकील ने माना है कि याचिकाकर्ता की स्थिति, जैसा कि उनके वरिष्ठ वकील ने बताया है, वह तथ्यात्मक रूप से सही है। इन तथ्यों को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता को चिकित्सीय आधार पर सजा से राहत (सजा पर रोक) देने के पक्ष में हैं। गुजरात राज्य की ओर से पेश हुईं वकील स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन उन्हें चिकित्सीय आधार पर सजा पर रोक लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की सजा पर रोक लगा दी।

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अपील की सुनवाई तेजी से होगी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपीलीय ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ दाखिल अपीलों पर पहले सुनवाई होनी चाहिए। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाए, जहां नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करे। अदालत ने अपीलों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया है। पहली श्रेणी में उन लोगों की अपीलें होंगी, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। दूसरी श्रेणी में उन लोगों की अपीलें होंगी, जो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने को चुनौती दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि दूसरी श्रेणी के मामलों में उतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि करीब 38 लाख अपीलें दाखिल हुई हैं।

खतरे पर एनसीटीएयू क्या बोला?

व्हाट्सएप अकाउंट में सेंध, पढ़े जा रहे दूसरे यूजर के मैसेज!

नई दिल्ली। व्हाट्सएप पर निजी बातचीत और जरूरी जानकारी साझा करने वाले लोगों के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक अहम चेतावनी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (ड्ब्4ष्ट) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) ने व्हाट्सएप वेब के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। यूनिट के मुताबिक, कुछ खास परिस्थितियों में प्रमाणित व्हाट्सएप वेब सेशन का गलत इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति के अकाउंट तक बिना अनुमति पहुंच बनाई जा सकती है। इससे आपकी निजी चैट, संपर्क और ग्रुप की बातचीत दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा सकती है। एनसीटीएयू के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप वेब सेशन तक किसी दूसरे व्यक्ति की अनधिकृत पहुंच बन जाती है, तो वह अकाउंट का इस्तेमाल यूजर की तरह कर सकता है। वह निजी मैसेज पढ़ने के साथ दूसरों को आपकी पहचान से मैसेज भी भेज सकता है। इसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप में चल रही बातचीत तक पहुंच बना सकता है। साइबर अपराधी इस भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। वे आपकी पहचान का इस्तेमाल करके फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और दूसरी तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं। यानी



आपके नाम से भेजे गए मैसेज पर परिचित लोग भरोसा कर सकते हैं और ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर यूनिट ने खास तौर पर ऑफिस, साझा और सार्वजनिक कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने को कहा है। ऐसे कंप्यूटरों का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, इसलिए उन पर लॉग-इन किया गया अकाउंट असुरक्षित हो सकता है। साइबर कैफे, सार्वजनिक कियोस्क, होटल के बिजनेस सेंटर और किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लिए गए कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब खोलने से बचना चाहिए। सरकारी, वित्तीय, संगठन से जुड़ी या गोपनीय जानकारी का आदान-प्रदान भी कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब के जरिए नहीं करना चाहिए।

आधिकारिक और संवेदनशील काम के लिए संगठनों को भी इससे बचने की सलाह दी गई है। साइबर यूनिट ने यूजर्स को अपने अकाउंट की असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी है। अगर आपके अकाउंट से ऐसा कोई मैसेज भेजा जाता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, या आपके संपर्कों की ओर से किसी अजीब मैसेज का जवाब आता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी गतिविधियों को गंभीरता से लेना चाहिए। संगठनों को भी सलाह दी गई है कि वे ऑफिस में आधिकारिक और संवेदनशील काम के लिए व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल न करें। अगर इसका इस्तेमाल जरूरी हो, तो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड अपनाएं और हर बार काम पूरा होने के बाद लॉग-आउट करें। हालांकि, प्राइवेट मोड केवल अतिरिक्त सावधानी है, सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं। अपनी डिजिटल पहचान और निजी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए इन सावधानियों का पालन जरूरी है।

व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

एनसीटीएयू ने यूजर्स को कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। इनका पालन करके अकाउंट के गलत इस्तेमाल का खतरा कम किया जा सकता है।

हमेशा लॉग-इन न रखें- जरूरत पूरी होने के बाद व्हाट्सएप वेब सेशन खुला न छोड़ें, खासकर ऑफिस या साझा कंप्यूटर पर।

हर बार लॉग-आउट करें-काम खत्म होने पर खुद लॉग-आउट करें। केवल ब्राउजर की विंडो या टैब बंद करना लॉग-आउट नहीं माना जाना चाहिए।

एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 27 नवम्बर को

उत्तर बस्तर कांकेर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोड़ेजुंगा कांकेर में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 27 नवम्बर को सुबह 11 से अपरान्ह 03 बजे तक किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 169 रिक्तियों के आधार पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी श्री बी.आर. ठाकुर ने बताया कि उक्त प्लेसमेंट कैम्प में सिक्युरिटी गार्ड के 100 पद, बैंक असिस्टेंट के 30, मार्केटिंग एक्सक्युटीभ के 09, हाउस कीपिंग स्टॉफ के 10 और इन्शुरेंस एडवाईजर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक उक्त रोजगार मेला में उपस्थित होकर अथवा ई-रोजगार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन https://erojgar.cg.gov.in/ पर अपना सम्पूर्ण बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियोक्ता द्वारा प्राथमिक चयन कर साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसकी सूचना फोन के माध्यम से आवेदक को दिया जाएगा।

बालोद जिले में गांजे की बड़ी खेप जब्त, 2 गिरफ्तार

बालोद। जिले में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के खप्परवाड़ा गांव में एक घर से पुलिस ने दबिश दी। जहां से एक क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, सनौद पुलिस को गिरफ्तार किए गए एक आरोपी से पूछताछ के दौरान सूचना मिली थी कि गुंडरदेही थाना क्षेत्र के खप्परवाड़ा गांव में घर में बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलते ही सनौद पुलिस और साइबर सेल की टीम सक्रिय हुई। एसपी किरण चव्हाण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग थानों की पुलिस टीम गठित की। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में खप्परवाड़ा के संबंधित घर पर दबिश दी गई। कार्रवाई में डीएसपी रैंक के अधिकारियों समेत करीब दर्जनभर पुलिस जवान शामिल रहे। पुलिस की यह कार्रवाई देर रात करीब 11 बजे तक चली। बताया जा रहा है कि बालोद जिले में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करने की कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की एंड टू एंड कार्रवाई में जुट गई है।

धान खरीदी से लेकर जिले के सभी विकास कार्यों की कलेक्टर बसंत ने की समीक्षा

धान खरीदी व्यवस्था एवं केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण



अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज समय-सीमा की बैठक में जिले में धान खरीदी व्यवस्था, जनहित से जुड़े मुद्दों, निर्माण कार्यों तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जनसमस्याओं के निराकरण में तत्परता बरतने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री प्रताप विजय खेस, नगर निगम आयुक्त श्री विनय अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में जिले के धान खरीदी केंद्रों में जारी धान खरीदी की केंद्रवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने किसानों के रकबा सत्यापन, अवैध रूप से धान खपाने की रोकथाम तथा खरीदी प्रक्रिया में सभी सुविधाओं के साथ पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी धान खरीदी केंद्रों का मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए एसडीएम, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विपणन अधिकारी एवं खाद्य अधिकारी को संयुक्त रूप से केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने तथा खरीदी की नियमित निगरानी करने कहा।

ईंट भट्ठों में श्रमिकों के बच्चों के लिए मिनी आंगनबाड़ी सुविधा

ईंट भट्ठों के निरीक्षण के संबंध में श्रम विभाग, डीपीओ एवं खनिज विभाग को संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईंट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को कार्यस्थल पर अस्थायी मिनी आंगनबाड़ी सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण करने कहा, ताकि बच्चों को पोषण एवं प्रारंभिक देखभाल की सुविधाएं मिल सकें।

पेयजल, सड़क, विद्युत एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा

इसके अलावा कलेक्टर ने जिले में पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, विद्युत आपूर्ति और हाईटेंशन तारों से संबंधित समस्याओं, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, वय वंदन कार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समन्वयपूर्वक निराकरण कर आवश्यक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शिक्षा एवं स्कूल भवन निर्माण कार्यों पर जोर

इसके अलावा शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीई अंतर्गत बच्चों के एडमिशन की जानकारी ली गई। उन्होंने सभी निजी संस्थानों को आरटीई अंतर्गत शाला छोड़ने वाले बच्चों के शाला छोड़ने के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए सात दिवस के भीतर शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल भवनों के निर्माण एवं अन्य शैक्षणिक अधोसंरचना संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने कहा।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण

सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान करने तथा शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक निराकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग, खरसिया नाका तथा एमजी रोड के सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने भू-अर्जन , सड़क निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाने तथा संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करने कहा।

ग्रामीण अधोसंरचना सहित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा

कलेक्टर ने सुग्घर छत्तीसगढ़ योजना के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनपदवार समीक्षा के दौरान पीएम जनमन योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों तथा आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा। जिले के विभिन्न ग्रामों में पुल-पुलिया निर्माण, भूमि विवादों के निराकरण, महतारी सदन, सीसी रोड निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने कहा।

कलेक्टर ने बालिका शौचालयों की जानकारी लेते हुए नए वर्ष में ग्रामों में स्वीकृत तथा निर्माणाधीन बालिका शौचालयों को पूर्ण करने तथा सभी विद्यालयों में दिसंबर तक बालिका शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामों में मुक्तिधाम निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके साथ ही सभी जनपदों में वीबी-जी राम जी योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए

बैलाडीला में मलबे का पहाड़ खिसकने से दहशत, जांच के लिए दंतेवाड़ा जाएगी कांग्रेस

दंतेवाडा। बैलाडीला में लौह अयस्क का बड़ा खदान है। खदान से हर दिन लाखों टन मिनरल्स निकाला जाते हैं। मिनरल्स निकालने जाने के दौरान सैकड़ों टन वेस्ट भी निकलता है। अब यही वेस्ट बड़ी समस्या बनती जा रही है। दरअसल, बैलाडीला में खनन अपशिष्ट (माइनिंग वेस्ट) का पहाड़ खिसकने से वहां पर दहशत फैल गई। पर्यावरण से जुड़ा खतरा बताकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस की एक 7 सदस्यीय टीम बैलाडीला में खनन अपशिष्ट का पहाड़ कैसे खिसका इसकी जांच करने जाएगी। जहां पर पहाड़ खिसका है वह डिपॉजिट 14 में आता है। कांग्रेस का कहना है, %%वहां पर हजारों पेड़ पौधे और प्राकृतिक जलधाराओं से स्रोत हैं, पहाड़ के खिसकने से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस की जांच टीम के समिति संयोजक विधायक लखेश्वर बघेल बनाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मलबे का बना पहाड़ खिसककर लोहागांव पहुंच मार्ग तक आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। कांग्रेस की जांच टीम जल्द ही प्रभावित इलाके में पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट लोगों से बातचीत के बाद तैयार करेगी। कांग्रेस ने इस घटना को केवल पहाड़ी से मलबा खिसकने की सामान्य घटना नहीं बताया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय माना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अविलंब प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें। इस दौरान एनएमडीसी प्रबंधन के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामवासियों से मुलाकात कर घटना के कारणों, मौजूदा हालात और संभावित नुकसान की जानकारी जुटाई जाएगी। समिति को मौके पर पहुंचकर यह भी समझने के निर्देश दिए गए हैं कि खनन अपशिष्ट का इतना बड़ा हिस्सा किन परिस्थिति में खिसका और इससे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर कितना प्रभाव पड़ा। समिति प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं, आवागमन में आई बाधा और प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़े संभावित प्रभाव की जानकारी भी जुटाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट को समिति के सदस्य अपने नेता को सौंपेंगे। बैलाडीला क्षेत्र देश के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में शामिल है। यहां लंबे समय से खनन गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसे में डिपॉजिट-14 में टेलिंग्स का मलबा खिसकने की घटना ने खनन अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन, पर्यावरणीय निगरानी और सुरक्षा इंतजामों पर बहस शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक जलधाराओं, नालों और जंगलों को संभावित नुकसान की आशंका के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निर्धारित उपायों का कितना पालन किया जा रहा है।



कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति में इनके नाम शामिल

लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक- जांच समिति के बनाए गए संयोजक, विक्रम मंडावी, विधायक- जांच टीम के सदस्य, देवती कर्मा, पूर्व विधायक- जांच टीम की सदस्य ,रेखचंद जैन, पूर्व विधायक जांच टीम के सदस्य, मोहम्मद शकील रिजवी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा जांच टीम के सदस्य, लालू राठौर, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर, जांच टीम के सदस्य, अवधेश गौतम, पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा जांच टीम के सदस्य

शिक्षक पर धर्मांतरण का आरोपः बजरंग दल ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के ग्राम बहरी झोरकी में कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बहरी झोरकी में शासकीय शिक्षक कृष्णा लाल लकड़ा और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण कराए जाने की शिकायतें और जानकारियां सामने आई हैं। इस प्रकरण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों



और हिंदू समाज के लोगों में चिंता और असंतोष व्याप्त है।?शासकीय शिक्षक कृष्णा लाल लकड़ा की भूमिका की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ उनके परिवार की भी जांच की जाए।कथित धर्मांतरण के आरोपी के तौर पर ?ग्राम बहरी झोरकी निवासी ध्यान सिंह केरकेट्टा, नितेश केरकेट्टा, विजय केरकेट्टा और बिटकू लाल की कथित भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाए। संबंधित व्यक्तियों के आय के स्रोत, आय-व्यय और संपत्ति की जांच सक्षम विभाग से कराई जाए, ताकि संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई हो सके। संबंधित व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता और जारी होने की प्रक्रिया की जांच राजस्व अधिकारी से कराई जाए। अनियमितता पाए जाने पर प्रमाण पत्र निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ?ग्राम बहरी झोरकी में कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो। दोष प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम गठित की जाए और जांच की प्रगति से शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए।

अम्बिकापुर से बिहार जा रही यात्री बस पेड़ से टकराई

सूरजपुर। जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। अंबिकापुर से बिहार के सासाराम से जा रही यात्री बस तड़के दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे के दौरान बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। इस हादसे में लगभग 15 यात्री घायल हुए है।प्रतापपुर के शिवपुर मार्ग के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

तेज रफ्तार बस का टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा



गई। सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दर्जन भर से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई। स्थानीय लोगों ने प्रतापपुर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

हादसे में बस चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बस को काटकर बाहर निकाला गया। बस कंडक्टर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।सभी घायलों को पहले प्रतापपुर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से चार गंभीर घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची प्रतापपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग में जीपीएम जिले के खिलाड़ियों ने जीते 6 पदक

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 26वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर जिले एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से जिले के तीन खिलाड़ियों रोहित कुमार, जन्तराम पनिका एवं मोहनी मरावी ने भाग लेकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। प्रतियोगिता में रोहित कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण एवं एक रजत पदक जीते। उन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक एवं 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में शानदार समय दर्ज कर रिकॉर्ड भी बनाया। इसी तरह जन्तराम पनिका ने दो कांस्य पदक तथा मोहनी मरावी ने एक कांस्य पदक अर्जित कर जिले का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर लौटे तीनों खिलाड़ियों ने कलेक्टर विजय दयाराम के. से सौजन्य भेंट की। कलेक्टर ने खिलाड़ियों की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त कर बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की कामनी की।

हमले में 35 वर्षीय युवक गंभीर घायल, रायगढ़ रेफर

रायगढ़। जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के लैलूंगा रेंज का है, जहां देर रात खेत में अपनी फसल देखने गए एक ग्रामीण का सामना दंतैल हाथी से हो गया। हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, लैलूंगा रेंज के लिबरा परिसर अंतर्गत ग्राम नारायणपुर में पिछले कुछ दिनों से एक अकेला हाथी विचरण कर रहा है। इसी बीच बीती रात करीब 11 बजे गांव का रहने वाला जलधर लकड़ा (35 वर्ष) अपनी फसल देखने खेत की ओर गया था। इसी दौरान अचानक उसका सामना दंतैल हाथी से हो गया। इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाता, हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद परिजन तत्काल घायल जलधर को उपचार के लिए लैलूंगा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया।

रायगढ़ में एक ही दिन में 631 वाहन चालकों पर कार्रवाई

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस द्वारा जिलेभर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने गत दिनों आयोजित क्राइम मीटिंग में जिले में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी थाना प्रभारियों को प्रतिदिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने विशेष रूप से तेज गति से वाहन चलाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्ती बरतने के साथ ही यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक करने कहा था। रायगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तेज गति से वाहन चलाने, ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट वाहन चलाने, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन, बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने सहित मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 631 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 4 लाख रुपये का चालान किया गया।

चावल कारोबार में 60 लाख की धोखाधड़ी, अब गया जेल

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में चावल के कारोबार से जुड़ी 60 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुरूद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महासमुंद के राइस मिलर विनय अग्रवाल को हिरासत में लिया है। आरोपी पर चावल की खरीदी-बिक्री के एक करोड़ रुपये के सौदे में शेष 60 लाख रुपये के भुगतान को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आर्थिक धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने रविवार रात महासमुंद में दबिश देकर उसे पकड़ा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे लेनदेन की जांच की जा रही है। एक करोड़ रुपये में तय हुआ था चावल का सौदा पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, कुरूद के अमलीडीह स्थित डीएमएच एग्रोटेक राइस मिल की संचालक उर्मिला शर्मा ने महासमुंद के सालासर बालाजी फूड्स के प्रोपराइटर विनय अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि अप्रैल 2023 में दोनों फर्मों के बीच चावल की खरीदी-बिक्री को लेकर एक करोड़ रुपये का सौदा तय हुआ था।

कोरबा में 100 परिवारों ने फिर अपनाया हिंदू धर्म

कोरबा। कोरबा जिले के घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित हिंदुत्व रक्षक सम्मान समारोह के दौरान 100 परिवारों के करीब 500 सदस्यों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। आयोजकों के अनुसार, इन परिवारों ने पहले ईसाई धर्म अपना लिया था और अब अपनी मूल धार्मिक परंपराओं में लौटने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज, अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और धर्मसेना के बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। समारोह में हिंदू धर्म में लौटने वाले परिवारों का पांव पखारकर स्वागत किया गया। घंटाघर ओपन थिएटर में आयोजित हुआ समारोह हिंदुत्व रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने तथा घर वापसी अभियान से जुड़े लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान 100 परिवारों के 500 सदस्यों की धार्मिक परंपराओं में वापसी की रस्म पूरी कराई गई।

रोजगार सहायकों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

1 दिसंबर तक मांगें पूरी करने का दिया अल्टीमेटम

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के रोजगार सहायक अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के सामने आंदोलन कर रहे हैं। मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज रोजगार सहायक संघ ने 1 दिसंबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है।आंदोलन को लेकर बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण में संघ के प्रांतीय आह्वान पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार सहायकों ने शामिल होकर आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की।संघ की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिनमें रोजगार सहायकों को सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करना, सहायक सचिव का दर्जा देते हुए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती में रोजगार सहायकों को शत-प्रतिशत अवसर



देते हुए नियुक्ति प्रदान करना शामिल है। पदनाम के लिए करना पड़ रहा संघर्षबैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि रोजगार सहायक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और मनरेगा के क्रियान्वयन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आज भी अपेक्षित वेतनमान, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक पदनाम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शासन की अलग-अलग योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पंचायत स्तर पर कामकाज को गति देने में रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर अब तक ठोस पहल नहीं हुई है- नरेंद्र वर्मा, रोजगार सहायक बेमेतरा

30 नवंबर तक यदि मांगों के संबंध में सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 1 दिसंबर से प्रदेशभर के रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। इस आंदोलन में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के कर्मचारी शामिल होंगे।

संघ के आंकड़ों के मुताबिक, बेमेतरा जिले में लगभग 350 रोजगार सहायक और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 8 हजार रोजगार सहायक प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के एक साथ आंदोलन में उतरने से पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं और सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

140 पेटी गोवा शराब के साथ 3 गाड़ियां जब्त

जगदलपुर। बस्तर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरभा थाना क्षेत्र के छोटे कड़मा में परिवहन के दौरान मध्यप्रदेश की गोवा ब्रांड विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कार्रवाई में कुल 140 पेटी और 10 शराब की बोतल अलग से जब्त की गई है। जिसकी कुल मात्रा 1261.8 बल्क लीटर बताई गई है। इस मामले में दो नाबालिग के साथ एक 18 वर्षीय युवक भी शामिल पाया गया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने मौके से कुल 7010 गोवा ब्रांड विदेशी मदिरा जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 9 लाख 46 हजार 350 रुपये आंकी गई है। शराब के



परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं। आबकारी अधिकारी अंकित सिंह राठौर ने बताया कि 21 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर दरभा थाना क्षेत्र के छोटे कड़मा में रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान एक नाबालिग वाहन में संदिग्ध अवस्था में मिला। वाहन की तलाशी लेने पर 15 पेटी गोआ ब्रांड की शराब डिक्की से बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान गाड़ी में बैठा सुनील सेठिया निवासी राजुर मौके से फरार हो गया। इसके साथ ही काले रंग की गाड़ी में 2 और लोगों को पकड़ा गया, उसमें भी एक नाबालिग था, वहीं दूसरा प्रवीण बघेल निवासी चितापूर इन दोनों के पास 1 पेटी गोआ ब्रांड की शराब बरामद की गई। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि गिट्टी खदान के रास्ते पर सुनील सेठिया ने शराब छुपा कर रखी है। तलाशी लेने पर अशोक लीलैंड की वाहन संदिग्ध अवस्था मे मिली, जिसमें 124 पेटी गोआ ब्रांड मध्यप्रदेश की शराब बरामद की गई। इस प्रकार 1261.8 लीटर मध्यप्रदेश की शराब बरामद की गई है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब और जब्त वाहन का बाजार मूल्य 20 लाख 96 हजार 350 रुपये आंकी गई है।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा कार्यालय में तैयार हुआ यूसीसी ड्राफ्टः बैज, भाजपा ने किया पलटवार



रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसकी ड्राफ्टिंग बीजेपी कार्यालय में की गई है। वहीं बैज के बयान पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने सवाल किया कि क्या बैज जैसे चाहेंगे, क्या वैसा नियम-कानून बनेगा। दीपक बैज ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया था और विभिन्न वर्गों से सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की राय को नजरअंदाज किया गया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी वर्गों ने यूसीसी का विरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता छत्तीसगढ़ और यहां के आदिवासी समाज के हित में नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूसीसी की ड्राफ्टिंग बीजेपी कार्यालय में ड्राफ्ट हुई है। वहीं, दीपक बैज के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दीपक बैज की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि दीपक बैज जैसा चाहेंगे, वैसा नियम कानून बनेगा क्या ?

नंदकुमार साय हुए चोटिल, हेलिकॉप्टर से गृह ग्राम से रायपुर लेकर आए सीएम साय



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर में अपने साथ रायपुर लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री साय ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दो दिन पहले नंदकुमार साय फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके पैर में चोट आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल जशपुर प्रवास के दौरान उनके निवास के समीप ही एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था। इस दौरान वे रात में नंदकुमार साय के निवास पहुंचकर उनसे मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पैर में चोट के कारण नंदकुमार साय को चलने-फिरने में तकलीफ हो रही थी। आज उन्हें रायपुर आना ही था, इसलिए नंदकुमार साय को भी अपने साथ हेलीकाप्टर से रायपुर ले आए, ताकि उन्हें यात्रा में असुविधा न हो और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उनके बेहतर उपचार के लिए रायपुर के बालाजी अस्पताल में व्यवस्था की गई है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने कहा, उनके आरोप में कोई सत्यता नहीं है। इस साल 360 धान खरीदी केंद्र नया बनाए हैं। कुल 3100 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की तकलीफ ना हो।

रायपुर में 6 दिसंबर को श्री पुनरासर बालाजी की भव्य ज्योत का होगा आयोजन

रायपुर। राजधानी रायपुर में चौथी बार श्री पुनरासर बालाजी की भव्य ज्योत का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम रविवार 6 दिसंबर को विधानसभा मार्ग स्थित अमर मेरीज पैलेस में आयोजित किया जाएगा। पिछले दिनों कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कमेटी सदस्यों की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सभी सदस्य घर-घर जाकर हनुमान भक्तों को निमंत्रण और सवामणी प्रसाद कूपन वितरित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से रमेश सोमानी, हेमंत तोतला, प्रहलाद पेड़ीवाल, पंकज पेड़ीवाल, अरविंद डागा, शिवनारायण मूंधड़ा, मनीष चांडक, मुकेश श्यामसुखा, संजय वैद, रमेश झंवर, सुरेश मोहता, पवन करनानी, संदीप डागा, रामेश्वर लाहोटी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ भजनों का भी आयोजन किया जाएगा। कोलकाता की श्री सीताराम सत्संग समिति दोपहर 1 बजे से सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत शुरू करेगी। वहीं शाम 7:30 बजे से श्री पुनरासर धाम के मुख्य पुजारी श्री रतनलाल बोथरा द्वारा बाबा की भव्य ज्योत की जाएगी। ज्ञात हो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में श्री पुनरासर बालाजी धाम स्थित है, जहां बालाजी अपने वीर रूप में विराजते हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां की सेवा पूजा हनुमान जी के आदेश से ओसवाल समाज के बोथरा परिवार के लोग करते हैं।

मेडिकल पीजी में एडमिशन के लिए एमडी-एमएस की दूसरी काउंसिलिंग लिस्ट जारी

रायपुर। मेडिकल पीजी में एडमिशन के लिए एमडी-एमएस की दूसरी काउंसिलिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 299 अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट की गई है। इनमें 40 अभ्यर्थियों की सीट अपग्रेड हुई है। यानी पहले राउंड में मिली सीट से बेहतर विकल्प वाले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मौका मिला है। अभ्यर्थियों को 25 से 30 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एमएससी नर्सिंग के लिए भी करीब 300 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में 97 नई सीटें भी शामिल की गई हैं। ये सीटें पहले राउंड की काउंसिलिंग के दौरान स्वीकृत हुई थीं। नई सीटें मिलने के बाद रिजर्वेशन रोस्टर के आधार पर कोटा तय किया गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। पहले राउंड में खाली रह गई सीटों को मिलाकर रविवार को 299 सीटों का अलॉटमेंट किया गया।

संविधान का अपमान बार-बार कांग्रेस पार्टी ने किया है : अरुण साव

डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को भाजपा कार्यालय (एकात्म परिसर) में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था और हमारा यह संविधान 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। साव ने कहा कि जब हमने संविधान को अपनाया, तो उसे हमारे इतिहास से दूर कर दिया गया था, जिसे 2015 से फिर से प्रारंभ कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संविधान के प्रति और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान को व्यक्त किया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू, प्रदेश मंत्री जयंती पटेल, जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयोग अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही, जिला उपाध्यक्ष अकबर अली मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2015 में जब संविधान दिवस मनाने का निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इससे पहले बाबा साहेब की 125वीं जयंती का भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। देश और संविधान से जुड़ी किसी भी बात में जिसमें उस एक विशेष परिवार – गांधी-नेहरू परिवार का नाम नहीं होता है, उसका विरोध करते हैं। श्री साव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने देश के संविधान निर्माता का ही न केवल सम्मान किया, वरन् देश के संविधान के मौलिक तत्वों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 26 नवंबर, जब देश के संविधान को अंगीकार किया गया, उसे संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। आज संविधान की चर्चा पूरे देश में होती है, हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो क्षमता है, जो ताकत है, वह जन-जन तक पहुँचे, संविधान निर्माण के समय डॉ. अंबेडकर के जो विचार थे, जिन विचारों को लेकर संविधान का निर्माण हुआ, वह विचार जन-जन तक पहुँचे और आज मोदी सरकार, डॉ. अंबेडकर के विचारों पर चलकर आज देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर काम कर रही है। जिस संविधान निर्माता का जिस पार्टी ने सम्मान न किया हो, उस पार्टी से अपेक्षा कैसे करोगे कि वह संविधान का सम्मान करेगी। संविधान का अपमान बार-बार किसी राजनीतिक दल ने किया है, तो उस राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस पार्टी है।

साव ने कहा कि संविधान दिवस का दिन अपने संवैधानिक मूल्यों – न्याय, समानता और विविधता में एकता के महत्व की याद दिलाता है। संविधान दिवस हमें अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर सभी को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए श्री साव ने कहा कि संविधान निर्माण में हमारे छत्तीसगढ़ के भी महान विभूतियों ने योगदान दिया है। इनमें घनश्याम सिंह गुप्त, पं.रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, पं. किशोरी मोहन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोताई का योगदान रहा है। श्री साव ने सभी महान विभूतियों को नमन करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति युवाओं को जागरूक करें।



साव ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य उनके विचारों को स्मरण करना और उन विचारों को जन-जन तक पहुँचाना है। संवैधानिक मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता आए, इसी ध्येय को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साव ने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा और अपने सभी सदस्यों के अमूल्य सुझावों को समाहित करते हुए संविधान का निर्माण किया और जिन-जिन लोगों ने संविधान के निर्माण में योगदान किया है, उन सभी को नमन और प्रणाम है। आज भारत का संविधान दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है और यह केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, वास्तव में यह भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, यह हमारे देश की 140 करोड़ जनता की आत्मा है, जो संविधान के रूप में हम सबके सामने है।

साव ने कहा कि यह संविधान हमें अधिकार देता है, तो अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बड़ी आजादी दी है, तो उसमें मर्यादा भी बताई गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत के शब्द हम भारत के लोग हमें यह एहसास कराते हैं कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग और बेहतर बनाती है। आज की वैश्विक स्थिति में पूरे विश्व की नजर भारत पर है और यह केवल और केवल भारत के संविधान की ताकत है, भारत की विशेषताओं के कारण आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया में हमें बहुत उम्मीद से देखा जा रहा है। एक ऐसा देश जिसके बारे में यह आशंका जताई जा रही थी कि वह अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, इसके बारे में कहा जाता था कि बिखर जाएगा, आज अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सबके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है और आज श्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया के निर्माण का, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर उसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को जितना सम्मान दिया, उतना कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूर्व सरकारों ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कद को छोटा करने की कोशिश की, ताकि उनका कद किसी नेहरू-गांधी परिवार के समकक्ष खड़ा न हो पाए।

छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारों के आरोप पर भाजयुमो अध्यक्ष ने कसा तंज



रायपुर। डबल इंजन सरकार के बावजूद छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी वाले कांग्रेस के बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हेमांग जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस के लोग बेरोजगार हैं। जनता ने कांग्रेस को फ्री कर दिया है। 'युवा संवाद' कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हेमांग जोशी ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज देश का युवा गिवर बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जितना बेरोजगार कोई नहीं है। इसके साथ राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर टिपण्णी को लेकर डॉ। हेमांग जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के लेवल पर जाकर बात करें तो शर्म आती है। राहुल गांधी की बात देश का कोई युवा नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी ने अपने प्रवास की वजह बताते हुए कहा कि संगठनात्मक प्रवास में दौरा हुआ है। युवा खिलाड़ियों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। नशा मुक्त विकसित भारत का अभियान चल रहा है। नशा मुक्त अभियान के तहत सही जानकारी युवाओं को मिल सकता है तो वो है खेल। युवा फिटनेस का ध्यान रख पाएंगे तो नशे से दूर रहेंगे।

धान खरीदी में भारी अनियमितता, त्रुटि सुधरवाने भटक रहे किसानः दीपक बैज



रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कि 3100 उपार्जन केन्द्रों में से अब तक लगभग 1 हजार में धान खरीदी शुरू ही नहीं हो पाया है। तौलाई, बारदाना, टोकन की समुचित व्यवस्था नहीं है। अनेको किसानों का रकबा पोर्टल में शून्य कर दिया गया है, इन किसानों को न आदान सहायता मिल पायेगा और न ही इनका धान एमएसपी पर खरीदी हो पायेगी। कई खेतो में धान के फसल को दिगर फसल दर्ज कर दिया गया है, कई किसानों का रकबा कम दिखाया जा रहा है, त्रुटि सुधारी नहीं जा रही है, ऐसे में किसान भटक रहे है यह सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर नही है। एम महिने बाद पटवारियो की हड़ताल समाप्त हुई है। सरकार राजस्व अमले को निर्देशित करें कि किसानों के नामांकन, बंटवारे, खसरा खतौनी की दुस्ती तुरंत करें। ताकि किसान आसानी से धान बेच सकें।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद विगत 8 सितंबर 2026 से खाली है, पिछले ढाई महिने से सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार स्थगित किये जा रहे है। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के नाम पर प्रदेश के युवाओ से वादा किया गया था कि यूपीएससी पैटर्न पर पीएससी भर्ती परीक्षा होगी, कया यही यूपीएससी पैटर्न है? 2025 का पीएससी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू इसी के चलते अनिश्चित काल के लिये रोक दिया गया है, यह सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं से विश्वासघात कर रही है। 75 दिनों से पीएससी का सारा काम काज ठप्प पड़ा है। सरकार एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 26 नवंबर को राजधानी में संविधान बचाओ मार्च आयोजित है। इसमें प्रदेश भर के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। पिछले एक दशक से देश के संविधान पर संविधानिक संस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे है। यह मार्च देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिये है। कांग्रेस पार्टी देश के सभी प्रदेश मुख्यालयों में संविधान की रक्षा के लिये यह मार्च निकालने जा रही है।

घरेलू हिंसा को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए: डेका

■ राज्यपाल मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित कार्यशाला मे शामिल हुए



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि मानव तस्करी और घरेलू हिंसा गंभीर सामाजिक समस्याएं हैं। इन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कानूनों का सख्ती से पालन, संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रियता और समाज की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। घरेलू हिंसा को किसी भी स्थिति में सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों का निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुदाय के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। राज्यपाल श्री रमेन डेका सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा विषयक प्रशिक्षण सह कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। वे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि मानव तस्करी आज खतरनाक रूप ले चुकी है। अब इसका संबंध केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव अंगों की मांग के कारण भी इसकी घटनाएं सामने आ रही हैं। यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। श्री डेका ने कहा कि पहले संयुक्त परिवारों की व्यवस्था थी, लेकिन अब एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। घरेलू हिंसा पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियां भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार केवल गृहिणियां ही नहीं, बल्कि बाहर जाकर काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा को किसी भी प्रकार की लत की तरह ही गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति, परिवार और समाज सभी पर पड़ता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना होगा। परिवार के नैतिक मूल्यों और सामाजिक वातावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन मामलों में पारिवारिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आती हैं, उनमें उचित काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को समझकर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस दिशा में पुलिस, न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त पर सरकार सख्तः जायसवाल



रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सरकार बड़ा कदम उठाते हुए अस्पताल का लाइसेंस कैंसल करने जा रही है, यही नहीं प्रकरण में संलिप्त डाक्टरों की डिग्री भी फ्रीज की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मीडिया से चर्चा में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल का लाइसेंस कैंसल किया जाएगा। इसके साथ संलिप्त डाक्टरों की डिग्री भी फ्रीज की जाएगी। जिसने ये काम किया है, उनको ऐसी सजा दी जाएगी, जिसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी याद रखेगी।

वहीं कांग्रेस के पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एसआईटी जांच कराएंगे, और साथी ही और भी जांच होगी। कांग्रेस के समय का हॉस्पिटल है। शुभारंभ में कांग्रेस के मंत्री और विधायक गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस की कोई संलिप्तता है। मै किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन कांग्रेस इसमें किसी भी प्रकार से राजनीति न करे।

राजस्थान के निकाय चुनाव में भाजपा को मिली हार के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में दिसंबर में होने वाले निकाय चुनावों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राजस्थान की प्रकृति, छत्तीसगढ़ से अलग है। नगरीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। छत्तीसगढ़ में एक साल पहले ही निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। मन के लड्डू खाना कांग्रेस वाले भूल जाएं। सभी नगरीय निकाय में भाजपा की जीत होगी।

भाजपा में मोर्चा-प्रकोष्ठों को बूथ पर काम करने के मिल रहे टास्क पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में मोर्चा का गठन हुआ। रूटीन दौरा और सभी मोर्चा कार्य विस्तार पर काम कर रहे है। भाजपा में बूथों तक सभी मोर्चा काम करेंगे।

वहीं पटवारी हड़ताल किस शर्तों पर खत्म होने पर कांग्रेस के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। कांग्रेस को तकलीफ हुई होगी जब हड़ताल खत्म हुई। कांग्रेस चाहती है कि आम जनता परेशान हो। कांग्रेस मुख्यमंत्री का धन्यवाद करे। कांग्रेस बस किसान हितैषी बनने की बात करती है।

एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी क्षमता कई गुना बढ़ाने वाला सशक्त माध्यम : मंत्री वर्मा

■ उच्च शिक्षा विभाग और गूगल फॉर एजूकेशन के बीच एमओयू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को आधुनिक तकनीक, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग और गूगल फॉर एजूकेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ है। इस पहल के अंतर्गत प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई तकनीक के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने आज दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एमओयू हस्ताक्षर एवं एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग ज्ञान, नवाचार और तकनीक का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

मंत्री वर्मा ने कहा कि एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, रचनात्मकता और शिक्षण प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण साधन है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को केवल जानकारी ही नहीं देता, बल्कि उनमें सोचने, समझने, प्रश्न करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी विकसित करता है। एआई तकनीक शिक्षकों की इस भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि एआई तकनीक के माध्यम से प्राध्यापक बहुभाषी अध्ययन सामग्री तैयार कर सकेंगे। जटिल विषयों को सरल एवं रोचक तरीके से समझाने, बेहतर पाठ योजनाएं बनाने, विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं फीडबैक को अधिक प्रभावी बनाने तथा शोध कार्यों में नई संभावनाओं का उपयोग करने में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ जैसे विविध भाषाई, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में यह तकनीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पहल का लाभ केवल शिक्षकों और विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाविद्यालयों एवं विभागीय कार्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मिलेगा। एआई की सहायता से पत्राचार, दस्तावेज तैयार करने, सूचनाओं के विश्लेषण और विभिन्न कार्यालयीन कार्यों को अधिक सरल, व्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के साथ कार्यक्षमता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि प्रारंभिक कार्यशाला में रायपुर जिले के 22 महाविद्यालयों के 500 से अधिक शिक्षकों, अधिकारियों तथा उच्च शिक्षा संचालनालय के 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10 ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।



न्यायालय नायब तहसीलदार 80, रायपुर

मामले की श्रेणी: राजस्व

संदर्भः- जिला- रायपुर तहसील-रायपुर प.ह.न.-00069 अमलीडीह ग्राम के नामांतरण

पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-RD202627440725400025

ईश्तहार

तहसील रायपुर के प.ह.न. 00069 के अंतर्गत ग्राम अमलीडीह के वर्तमान भूमिस्वामी श्रीमति मंजू पिता/पति-पति शशीकांत गायकवाड पता-नि. हनुमान मंदिर के पास के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 148/4 (0.1090) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता श्री शशिकांत गायकवाड पिता/पति-श्री योगीराज गायकवाड पता-राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक के पास रायपुर, वरुण गायकवाड पिता/पति-श्री शशिकांत गायकवाड पता-राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक के पास रायपुर, अनुराग गायकवाड पिता/पति-श्री शशिकांत गायकवाड पता-राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक के पास रायपुर के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 07/12/2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय नायब तहसीलदार 8 रायपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिवक्ता / आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19/11/2026 को जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार

यूपी चुनाव : विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान!

राहिल नोरा चोपड़ा

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विपक्ष के भीतर सीट-बंटवारे को लेकर खींचतान सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक सहमति बनाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और राज्य में भाजपा की संख्या को सीमित कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अब 110 से ज्यादा सीटों की आकांक्षा रख रही है लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। सूत्रों ने संकेत दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक, 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम के इतर बातचीत हुई थी। कांग्रेस ने सीट.बंटवारे की बातचीत को संभालने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। इसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और के.सी. वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा-मोना और राज्य कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं। दोनों दलों के नेताओं ने संकेत दिया है कि जोर एक ऐसा समझौता करने पर होगा जो भाजपा को चुनौती दे सके और दोनों पक्षों ने सीट आबंटन के लिए जीतने की क्षमता को एक प्रमुख मानदंड बताया है। अपने गोरखपुर रोड शो के दौरान पी.डी.ए. (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रथ पर सवार होकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयास में उच्च जाति के राजपूत और ब्राह्मण समुदायों तक पहुंच बनाई। गोरखपुर जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्त्ता यात्रा के लिए पहुंचे। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''गोरखपुर यह संकेत दे रहा है कि भाजपा का गढ़ एक कठिन दौर देखने जा रहा है। इस बार गोरखपुर की जनता भाजपा को सभी 9 सीटों पर हराएगी। पूरे गोरखपुर मंडल का एकजुट पी.डी.ए. प्रभावशाली लोगों को हराएगा।'' सपा प्रमुख ने चौरी-चौरा में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। एक प्रभावशाली राजपूत नेता, सिंह ने भाजपा के समर्थन में उच्च जातियों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा के उन्हें चौरी-चौरा से मैदान में उतारने की संभावना है, जिससे उच्च जातियों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद, रामपुर में मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा के समीकरणों में वापस आ गए हैं। रामपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि 2027 का चुनाव एक इंकलाब होगा। ए.आई.एम.आई.एम. प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रामपुर की हालिया यात्रा पर, खान ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग 'हैदराबादी बिरयानी के मुकाबले पुलाव और मटन बिरयानी पसंद करते हैं'। कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना और सीट-बंटवारे की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि इसका वर्तमान नेतृत्व इसके पिछले नेतृत्व से बिल्कुल अलग है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल की घोषणा की, जिसके तहत 81 ए.आई.सी.सी. सचिवों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यात्मक विभागों में जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि 25 निवर्तमान सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया।

प्रजातंत्र की रक्षा, फासीवाद से मुकाबला समय की जरूरत

राम पुनियानी



भारत शिखर सम्मेलन 2026 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने और राजनेताओं और बड़े कारोबारी घरानों के बीच सांठगांठ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से फासीवादियों का शासन शुरू हुआ और तभी से भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। देश में इन दिनों एसआईआर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चल रहा है। नागरिकों ने अपने समूह गठित किए हैं और वे लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके चलते करोड़ों लोगों को वोट देने के अपने हक से महरूम होना पड़ा है।

वी-डेम इन्स्टीट्यूट के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स (चुनावी प्रजातंत्र सूचकांक) में दुनिया के 179 देशों में से भारत 106वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर 0.38 है जो कि 1975 में लगे आपातकाल के बाद से सबसे कम है। इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत एक पूर्ण प्रजातंत्र के स्थान पर निर्वाचित तानाशाही बन गया है। एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चलाए जा रहे आन्दोलनों को सरकार ने बहुत सख्ती से कुचला है। इन आन्दोलनों में शामिल लोगों की बुरी तरह पिटाई की गई। यह इस तथ्य के बावजूद कि वे लोग पूरी तरह अहिंसक थे। हमारे वर्तमान शासक मतदाता सूचियों से अपने विरोधियों के नाम गायब कर देना चाहते हैं ताकि भले ही उनकी लोकप्रियता कितनी ही कम हो जाए, वे चुनावों में जीत हासिल करते रहें।

इसके पहले भाजपा ने असम में एनआरसी के जरिए लोगों के वोट देने के हक को छीनने का प्रयास किया था। मगर उनके दावों के विपरीत असम में जिन 20 लाख लोगों के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे, उनमें से 12 लाख हिन्दू थे। भाजपा और उसकी सरकारें और नेता चिल्ला-चिल्लाकर कहते आ रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं। मगर तथ्य उनके दावों से मेल नहीं खाते। भारत के सत्ताधारी दल ने पहले ही न्यायपालिका में घुसपैठ बना ली हैं। न्यायपालिका पर उसका गहरा प्रभाव है। उसने अनेक स्वायत्त संस्थाओं को भी अपनी कठपुतली बना लिया है और वह हर तरह से लोगों के प्रजातांत्रिक हकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल द्वारा उन्हें फासीवादी कहना गलत नज़र नहीं आता।

आरएसएस के जन्मदाता समाज के वे वर्ग थे जो अंग्रेजों के राज के समय शुरू हुए प्रजातंत्र-समर्थक आंदोलनों के खिलाफ थे। वे लोग सामन्त, जमींदार और पुरोहित वर्ग के थे जो सामंतीकाल के ऊँच-नीच के मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे। ये लोग न केवल ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष से दूर रहे वरन उन्होंने सामाजिक-प्रजातांत्रिक सुधार आंदोलनों का भी विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि श्रमिकों को यूनियन बनाने का हक मिले, वे नहीं चाहते थे कि दलित और महिलाएं शिक्षा हासिल कर सकें। राष्ट्रीय आन्दोलन को दिशा देने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महती भूमिका थी जिसने देश को स्वाधीन और प्रजातांत्रिक बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

एक ओर मुस्लिम लीग और दूसरी ओर आरएसएस-हिन्दू महासभा अपने-अपने धर्मों के नाम पर अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे। आगे चलकर आरएसएस ने भारतीय संविधान और हमारे तिरंगे झंडे का विरोध किया, मनुस्मृति के मूल्यों को सही ठहराया और भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों की खिलाफत की।

वे फासिज्म पर मुग्ध थे और उन्होंने फासिज्म के मूल्यों और उसके काम करने के तरीकों की खुलकर प्रशंसा की। हिन्दू महासभा के डॉ. बी.एस. मुन्जे, मुसोलिनी से खासे प्रभावित थे। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन से वापिस लौटते हुए उन्होंने इटली में रूककर मुसोलिनी से मुलाकात की। वे इटली के फासीवादी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग बालीला से भी काफी प्रभावित थे। अपनी पुस्तक 'शेडो ऑफ स्वास्तिक' (स्वास्तिक की छाया) में मर्ज़िया केसारोली ने इस मुलाकात का विस्तार से विवरण दिया है। किताब का उपशीर्षक है ''भारतीय उग्र राष्ट्रवाद, इतालवी फासीवाद और नाज़ीवाद के परस्पर रिश्ते''।

इसी तरह आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ''व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड'' में जर्मनी के नाज़ीवाद की शान में कसीदे काढ़े हैं। वे लिखते हैं, ''...अपने राष्ट्र और संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने देश को यहूदियों से मुक्त कर पूरी दुनिया को चैंका दिया। यह राष्ट्रगौरव की उच्चतम अभिव्यक्ति है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि जिन नस्लों और संस्कृतियों में मूलभूत फर्क होते हैं वे कभी एक नहीं हो सकतीं। यह हिन्दुस्तान में हम लोगों के लिए एक सबक है जिसे हम सीख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं (व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइन्ड, पृष्ठ 27, नागपुर, 1938)। गोलवलकर ने ही हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के दो मूल सिद्धांतों की स्थापना की थी जो आज की भाजपा की राजनीति का आधार हैं। पहला, उन्होंने मुसलमानों, ईसाईयों और कम्युनिस्टों को देश का आंतरिक शत्रु बताया और दूसरा उन्होंने मनुस्मृति और उसमें निहित जातिगत और लैंगिक ऊँच-नीच का महिमामंडन किया।

सन 2014 के आमचुनाव में मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उनकी छवि को चमकाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों और एजेन्सियों की मदद ली गई। प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उनके आसपास एक आभामंडल निर्मित कर दिया गया। समाजविज्ञानी आशीष नंदी ने मोदी का एक इंटरव्यू लिया था जिसके बाद नंदी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मोदी एक खालिस फासीवादी हैं। फासीवादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपशब्द के रूप में नहीं बल्कि एक रोग की पहचान के रूप में किया था। नंदी लिखते हैं, ''करीब एक दशक पहले जब नरेन्द्र मोदी कुछ भी नहीं थे, वे एक छोटे-मोटे आरएसएस प्रचारक थे जो भाजपा में कोई पद हासिल करना चाहता था, उस समय मुझे उनका साक्षात्कार लेने का सौभाग्य मिला था। साक्षात्कार के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि वे एक खालिस, क्लिनीकल फासिस्ट हैं। मैं 'फासिस्ट' शब्द का इस्तेमाल एक गाली के रूप में नहीं करता। मेरे लिए वह एक रोग है जिसमें संबंधित व्यक्ति की विचारधारा और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के अलावा यह भी शामिल होता है कि उसका प्रेरणास्त्रोत कौन या क्या है।''

फासिस्ट सरकारें कार्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती हैं। भारत में लगभग सभी कार्पोरेट घरानों के अच्छे दिन चल रहे हैं और उनमें से एक की मानो लाटरी खुल गई है। नीतियां इस ढंग से बनाई जा रही हैं कि बड़ी कंपनियों के खजानों में अकूत धन आता रहे। आम आदमी का क्या होगा, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। भारत का फासीवाद जर्मनी से थोड़ा अलग है। जहां जर्मनी में नस्ल को नफरत फैलाने का हथियार बनाया गया था, भारत में इस काम के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग किया जा रहा है। राममंदिर, पवित्र गाय, लवजिहाद इत्यादि जैसे मुद्दों ने हिन्दू राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की है।

यह दिलचस्प है कि 2002 के कत्लेआम के बाद गुजरात की यात्रा पर आए एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल को वहां के हालात देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई दशकों पहले की जर्मनी में है (http://deshgujarat.com/2010/04/10/german-mps-mind-your-own-business/)। गुजरात में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में हिटलर का गौरवगान किया गया है। महात्मा गांधी ने आरएसएस को ''अधिनायकवादी सोच वाला साम्प्रदायिक संगठन'' बताया था।

आज जब हम एसआईआर की खिलाफत में खड़े हैं तब हमें यह समझना होगा कि भाजपा की सरकार कोई आम सरकार नहीं है। उसने सत्ता में आने के लिए हर संभव हथकंडों का उपयोग किया है और अब वह अनंतकाल तक के लिए सत्ता में बनी रहना चाहती है। यह इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में लोग उसकी जनविरोधी नीतियों के कारण उसके खिलाफ हो गए हैं। एसआईआर भारतीय प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसके जरिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है जो शायद भाजपा के खिलाफ मत देते। महत्वपूर्ण संस्थाओं और विभागों में अपने आदमियों की नियुक्ति कर पूरी व्यवस्था को पहले ही सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। संविधान और आजादी के आंदोलन के मूल्य आज गंभीर खतरे में हैं। मगर हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना होगी।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

और साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह भी सामान्य लक्षण विषयक होने के कारण अध्यवसाय रूप ही होता है।

प्रमाण व्यवस्था : इस प्रकार जैसा कि ऊपर कहा गया है, क्योंकि वस्तु दो प्रकार की हैं, एक बाह्य सत् स्वलक्षण और दूसरी मानस वस्तु अर्थात् सामान्य लक्षण, इसलिये ज्ञान भी दो प्रकार का है एक ग्रहण और दूसरा अध्यवसाय या अनुमान। ज्ञान के इन दोनों प्रकारों का भेद मौलिक और वास्तविक (fundamental and essential) है, वे दोनों प्रकार के ज्ञान परस्पर व्यावृत्त (mutually e&clusive) हैं, अर्थात् स्वलक्षण का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही हो सकता है और सामान्य लक्षण का ज्ञान अध्यवसाय या अनुमान से ही। एक के क्षेत्र में दूसरा जा ही नहीं सकता,

अर्थात् प्रत्यक्ष के क्षेत्र स्वलक्षण के विषय में अनुमान या अध्यवसाय नहीं जा सकता और अनुमान या अध्यवसाय के क्षेत्र सामान्यलक्षण में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता। इसी को प्रमाण व्यवस्था कहते हैं।

इसके विरुद्ध न्याय-वैशेषिक प्रमाण-संप्लव मानता है अर्थात् एक ही वस्तु अग्नि को हम प्रत्यक्ष से देख सकते हैं, उसका धूम से अनुमान कर सकते हैं, और शब्द प्रमाण द्वारा भी उसका ज्ञान हो सकता है। दिङ्नाग सम्प्रदाय और न्याय-वैशेषिक के बीच प्रमाण-संप्लव और प्रमाण-व्यवस्था को लेकर बहुत विवाद होता रहा है।

भारतीय दर्शन में प्रमाण व्यवस्था के सिद्धान्त का प्रथम संस्थापक दिङ्नाग ही था और भारतीय दर्शन में उस सिद्धान्त का वही महत्त्व है जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में काण्ट के द्वारा प्रतिपादित संवेदनात्मक (sensibility) और विचारात्मक (understanding) इन दो प्रकार के ज्ञानों के भेद का।

क्रमशः ...

औरंगजेब ने बेरहमी से करवाई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या

अनन्या मिश्रा



आज ही के दिन यानी की 24 नवंबर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की बेरहमी से हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते थे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का खुलकर विरोध किया था।

आज ही के दिन यानी की 24 नवंबर को सिखों के 9वें श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का निधन हो गया था। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी बलि दे दी थी। गुरु तेग बहादुर अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते थे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का खुलकर विरोध किया था। न सिर्फ सिख बल्कि हिंदु धर्म भी गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन करता है।

पंजाब के अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। इनके पिता सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद थे। गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम त्यागमल था।

बताया जा रहा है कि एक बार त्यागमल अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद किरतपुर जा रहे थे। इस दौरान त्यागमल की आयु 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा किया और अचानक से उन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ त्यागमल ने भी मुगलों का मुकाबला किया। इस छोटी उम्र में तेग बहादुर का साहस और जज्बा देखकर उनको त्यागमल से तेग बहादुर कहा जाने लगा।

मार्च 1632 में जालंधर के नजदीक करतारपुर में गुरु तेग बहादुर की शादी बीबी गुजरी से हुई। जिसके बाद वह अमृतसर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु, गुरु हरकृष्ण साहिब के निधन के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादर जी ने कई वर्ष बाबा बकाला नगर में घोर तपस्या की।

धर्म के प्रचार-प्रसार व लोक कल्याणकारी कार्य के लिए गुरु तेग बहादुर ने कई स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने आनंदपुर से कीरतपुर, सैफाबाद और रोपड के लोगों को संयम और सहज मार्ग का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वह खिआला पहुंचे, यहां से वह सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से वह कड़ामानकपुर पहुंचे और यहां साधु भाई मलूकदास का उद्धार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर प्रयागराज, बनारस, पटना और असम गए। इस दौरान गुरु तेग बहादुर ने सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए।

गुरु तेग बहादुर के समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब था। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के तौर पर थी। बताया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था।

मनीला में भारत का महा कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन!

किशन सनमुखदास भावनानी



वैश्विक स्तरपर 17 नवंबर 2026 का दिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है।फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक ओर 23वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने दक्षिण - पूर्व एशिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने का प्रयास किया, तो दूसरी मैं मीडिया के हवाले से बताना चाहूंगा कि मंगलवार 17 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे ओर क्वाड के मंच पर भारत, अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साझा हितों का प्रश्न वैश्विक चर्चा के केंद्र में रहा।मनीला में भारतीय पीएम,अमेरिकी राष्ट्रपति जापान की पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच क्वाड नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई।बैठक में भारतीय पीएम ने क्वाड को भारत के लिए एक रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारी बताते हुए कहा कि समुद्री सुरक्षा,भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं, नई तकनीकों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह हिंद-प्रशांत के लिए उपयोगी समाधान उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने अगले चरण के सहयोग के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा जताई।अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को महान नेता और अपना मित्र बताते हुए चारों देशों के संबंधों को मजबूत बताया।बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों,दुर्लभ मृदा तत्वों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमी कंडक्टर समुद्री निगरानी और संयुक्त समुद्री गश्ती अभ्यासों पर सहयोग की चर्चा हुई।ट्रंप ने नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्वरक कार्यक्रम की घोषणा भी की।यह बैठक 19 नवंबर की प्रस्तावित ट्रंप-शी जिनपिंग- पुतिन वार्ता से पहले विशेष कूटनीतिक महत्व रखती है।दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता प्रभाव होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा की चुनौती,वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित ट्रंप-शी जिनपिंग - पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक ने इस कूटनीतिक हलचल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत आसियान की आर्थिक ताकत और क्वाड की रणनीतिक साझेदारी के सहारे हिंद- प्रशांत में नया शक्ति संतुलन स्थापित कर पाएगा ?

साथियों बात अगर हम आसियान क्या है और भारत के लिए इसकी मित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? इसको समझने की करें तो,आसियान अर्थात दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति,राजनीतिक स्थिरता, व्यापार,निवेश और सामाजिक -सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।वर्तमान में इसके 11 सदस्य देशहैं,इंडोनेशिया,मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस म्यांमार, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर(तिमोर-लेस्ते) पूर्वी तिमोर अक्टूबर 2025 में इसका11वां सदस्यबना भारत आसियान का संवाद साझेदार और व्यापक रणनीतिक साझेदार है।भारत के लिए आसियान की मित्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण- पूर्व एशिया भारत को पूर्वी एशिया, प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक समुद्री व्यापार से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक सेतु है।

साथियों भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मूल उद्देश्य केवल पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना नहीं,बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक,तकनीकी,सामरिक और समुद्री संबंधों को मजबूत करना भी है।जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने में भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।122 अरब डॉलर से आगे बढ़ता आर्थिक रिश्ता और 2027 की ऐतिहासिक तैयारी, भारत और आसियान के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 123.12 अरब डॉलर रहा,जबकि 2025 -26 में यह बढ़कर 128.38 अरब डॉलर पहुंच गया। यह भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को दर्शाता है।भारत इस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी रसायन,खाद्य तेल,कोयला और ऊर्जा सेसंबंधित वस्तुओं का व्यापार करता है,जबकि भारतीय बाजार आसियान देशों के लिए भी विशाल अवसर उपलब्ध कराता है। दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा यानी आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते को अधिक संतुलित और कारोबार के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 को आसियान- भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2027 में दोनों के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। इसका अर्थ है कि भारत केवल वर्तमान व्यापारिक लाभ नहीं देख रहा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था तैयार करना चाहता है।

साथियों बात अगर हम दक्षिण चीन सागर पर भारत ने क्यों खोले अपने पत्ते ?इसको समझनेकी करें तो,इस पूरे सम्मेलन का सबसे संवेदनशील मुद्दा दक्षिण चीन सागर है।यह समुद्री क्षेत्र चीन, फिलीपींस,वियतनाम,मलेशिया, ब्रुनेई और अन्य देशों के क्षेत्रीय दावों के कारण लंबे समय से विवादों में है। चीन इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देश उसके दावों को चुनौती देते हैं। चीन और आसियान के बीच लंबे समय से आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने पर बातचीत चल रही है, जिसका उद्देश्य समुद्री विवादों को नियंत्रित करना और टकराव की आशंका कम करना है। नवंबर 2026 में लगभग 80 प्रतिशत मसौदे पर अस्थायी सहमति की खबर सामने आई, लेकिन इसकी कानूनी बाध्यता और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद बने रहने के कारण अंतिम समझौता नहीं हो सका। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इन क्षेत्रीय विवादों का पक्षकार नहीं है और न ही चीन-आसियान की आचार संहिता वार्ता में शामिल है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भारत इस क्षेत्र के घटनाक्रम से उदासीन है। भारत का स्पष्ट मत है कि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए।भारत चाहताहै कि कोई भी भावी आचार संहिता संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय(यूएनसीएलओएस) के अनुरूप हो और उन देशों के वैध अधिकारों को प्रभावित न करे जो इस वार्ता का हिस्सा नहीं हैं। भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का जलडमरूमध्य सहित इस क्षेत्र के समुद्री रास्ते भारत के ऊर्जा आयात, निर्यात और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से सीधे जुड़े हैं।

साथियों बात अगर हम गुरु नानक जयंती से पहलेमनीला के गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक संदेश- मनीला यात्रा का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचना भी रहा। 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर विश्वभर में सिख संगतों द्वारा प्रभात फेरियों, कीर्तन और सेवा गतिविधियों की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे आध्यात्मिक वातावरण के बीच प्रधानमंत्री का मनीला स्थित गुरुद्वारे में पहुंचना भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने वाला सटिका से अवसर बना। साथियों बात अगर हम क्वाड की महाबैठक और मोदी- ट्रंप संबंधों की नई परीक्षाको समझने की करें तो मनीला में क्वाड की बैठक भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है।क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भारत,अमेरिका,जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक सहयोग मंच है। इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन या नाटो जैसी व्यवस्था नहीं माना जाता, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति,सुरक्षा,आर्थिक सहयोग और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला मंच माना जाता है।

आज का इतिहास

1759 इटली में विसूवियस पर्वत शिखर पर ज्वालामुखी विस्फोट।
1859 चार्ल्स डार्विन की 'आन द ओरिजिन आफ स्पेशीज'का प्रकाशन।
1963 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑस्वाल्ड की हत्या की गई।
1871 नेशनल राइफल एसोसिएशन (एनवाईसी) का गठन।
1926 प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति।
1963 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑस्वाल्ड की हत्या की गई।
1966 कांगो की राजधानी किंसासा में पहला टीवी स्टेशन खुला।
1966 स्लोवाकिया के ब्रातिस्लवा के निकट बुल्गारिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 82 यात्रियों की मौत।
1986 तमिलनाडु विधानसभा में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया।
1988 दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लालदूहोमा को अयोग्य करार दिया गया।
1989 चेकेस्लोवाकिया में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे कर एक नए युग की शुरूआत की।
1992 चीन का घरेलू विमान दुर्घटनाग्रस्त, 141 लोगों की मौत।
1998 एमाइल लाहौद ने लेबनान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
1999 एथेंस में सम्पन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजुरानी देवी ने रजत पदक जीता।
2001 नेपाल में माओवादियों ने सेना व पुलिस के 38 जवान मार डाले।
2001 तुर्की की ग्रैंड नेशनल एसेम्बली ने देश के कानून में बदलाव करके महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुषों के बराबर ला खड़ा किया।
2006 पाकिस्तान और चीन ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किये तथा अवाक्स बनाने पर भी सहमति हुई।
2007 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ आठ वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश पहुँचे।
2008 मालेगाँव बम ब्लास्ट के मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एटीएस द्वारा अश्लील सीडी दिखाने का आरोप लगाया।
2018 भारतीय महिला मुक्केबाजी की सुपरस्टार एम सी मेरीकॉम (48 किग्रा) ने दसवीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
2020 भारत सरकार ने अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशिअर, कैमकार्ड समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगायी ।

कमियां गिनाने के बजाय राहुल गांधी देश को बताएं समाधान का रास्ता

कांतिलाल मांडोत

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन विपक्ष की राजनीति केवल आलोचना और आरोपों तक सीमित रह जाए तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगते हैं। देश को केवल यह बताने से काम नहीं चलेगा कि समस्याएं कितनी हैं, बल्कि यह भी बताना होगा कि उनका समाधान कैसे होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि देश के युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही है और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और चुनावी निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की समस्याओं को विदेश में गिनाने से उनका समाधान निकल आएगा? क्या राहुल गांधी के पास इन समस्याओं को दूर करने की कोई ठोस योजना भी है?

पिछले ग्यारह वर्षों में राहुल गांधी कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। अलग-अलग अवसरों पर उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता विदेश में भारत की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह देश की उपलब्धियों और संभावनाओं को भी सामने रखे। भारत केवल समस्याओं से घिरा देश नहीं है। यहां विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क, रेल और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। भारतीय युवा दुनिया के अनेक देशों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इन उपलब्धियों को स्वीकार करना किसी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि देश की प्रगति को पहचानना है।

राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के पास इसका क्या समाधान है। युवाओं को रोजगार चाहिए, केवल भाषण नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। सरकार से रोजगार के आंकड़ों और रिक्त पदों पर सवाल पूछना उचित है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी रोजगार नीति जनता के सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस यह बताए कि सत्ता में आने पर वह कितने रोजगार के अवसर पैदा करेगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाएगी। केवल निराशा का वातावरण बताने से युवाओं का विश्वास नहीं जीता जा सकता।

इसी तरह राहुल गांधी ने मतदाता सूची और



एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को हर उचित सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है। यदि कांग्रेस के पास मतदाता सूची में गड़बड़ी या चुनावी अनियमितता से जुड़े दस्तावेज हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप लगाने की स्वतंत्रता के साथ प्रमाण देने की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। बिना ठोस आधार के बार-बार संदेह जताने से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना करना राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। राजनीतिक विरोध और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और उसे उसे जनता के सामने रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर मुद्दे को मोदी, शाह या संघ के विरोध से जोड़ देने से जनता की मूल समस्याओं पर चर्चा कमजोर पड़ जाती है। देश की राजनीति व्यक्तियों के विरोध से आगे बढ़कर नीतियों और विकास के विकल्पों पर केंद्रित होनी चाहिए।

यहां एक बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से भी है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आखिर चुप क्यों रहते हैं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां विदेश में दिए गए बयानों की समीक्षा हो सके? क्या पार्टी नेतृत्व यह नहीं देखता कि इस तरह के बयानों से आम मतदाता के बीच क्या संदेश जाता है? किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व की बात महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पार्टी की सामूहिक जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। कांग्रेस को अपने नेता के हर बयान का समर्थन करने के बजाय तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन करना चाहिए। यदि किसी बयान से देश के भीतर या बाहर गलत संदेश जाता है तो उस पर स्पष्टता देना पार्टी का दायित्व है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार के अनेक आरोप और विवाद तत्कालीन सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गए थे। जनता ने चुनाव में अपना निर्णय सुनाया और सत्ता परिवर्तन हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस अपने संगठन और राजनीतिक कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं कर पाई। केवल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने से पार्टी का खोया जनाधार वापस नहीं आने वाला। जनता को यह जानना है कि कांग्रेस के पास देश के विकास, रोजगार, शिक्षा, किसान, मजदूर और मध्यमवर्ग के लिए कौन सी नई योजनाएं हैं।

राजनीति में विरोध करना आसान है, लेकिन जनता के सामने भरोसेमंद विकल्प रखना कठिन जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मतदाता अब केवल भाषण सुनकर निर्णय नहीं करता। वह काम, नेतृत्व, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को भी देखता है। विदेश में जाकर भारत की कमियां गिनाने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि उन कमियों को दूर करने के लिए उनकी पार्टी क्या करेगी। सरकार को भी आलोचनाओं का जवाब तथ्यों और अपने काम के आधार पर देना चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। देश की छवि किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। सरकार की गलतियों पर सवाल उठना चाहिए और विपक्ष की गलतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लगातार आरोप लगाने से मतदाताओं का दिल नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस को भी अपने नेतृत्व से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर पार्टी देश को कौन सा रास्ता दिखाना चाहती है। जनता को आरोपों की राजनीति नहीं, समाधान की राजनीति चाहिए। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी केवल समस्याओं की सूची पेश करने के बजाय उनका व्यावहारिक समाधान बताएं। लोकतंत्र में वही नेतृत्व लंबे समय तक जनता का विश्वास हासिल करता है, जो सवाल उठाने के साथ जवाब और विकल्प देने की क्षमता भी रखता हो।

हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे भारत-जापान

पवन पांडेय



भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच गहराते सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण संकेत है। इस वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भागीदारी बताती है कि भारत व जापान अब अपने रिश्तों को आर्थिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक-दूसरे के विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि यह मंच 2019 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और दोनों देशों की 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' को ठोस दिशा देता रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य व सामरिक सक्रियता, समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में, भारत और जापान का सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। बृहस्पतिवार को टोक्यो में हुई वार्ता में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने और भारत में सैन्य फायरिंग रेंज के उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया।

हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आर्थिक सुरक्षा के लिए जहां सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया, वहीं तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक और डिजिटल कनेक्टिविटी में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि जापान के पास उन्नत तकनीक, पूंजी और औद्योगिक अनुभव है, जबकि भारत के पास विशाल बाजार, युवा कार्यबल और बढ़ती आर्थिक क्षमता है।

दोनों देशों का सहयोग भारत की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे और रक्षा आत्मनिर्भरता को नई मजबूती दे सकता है। भारत और जापान की दोस्ती केवल दो देशों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन, किसी भी साझेदारी की सफलता महज घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से मापी जाती है। इसलिए, रक्षा तकनीक का हस्तांतरण, निवेश में वृद्धि, व्यापारिक संतुलन, आपूर्ति शृंखला की मजबूती और परस्पर जनसंपर्क बढ़ाना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्ष 2027 में भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह अवसर केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को नई ऊंचाई देने का भी होना चाहिए।

अखिलेश ने 24 सीटों का प्रस्ताव देकर कांग्रेस को यूपी में उसकी हैसियत दिखा दी

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अभी चुनावी बिगुल पूरी तरह बजा भी नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों की लड़ाई ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस 181 सीटों की मांग के साथ समाजवादी पार्टी के सामने बराबरी के साझेदार का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महज 24 सीटों के शुरुआती प्रस्ताव के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी। देखा जाये तो कांग्रेस के लिए यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की लड़ाई है। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह सवाल है कि जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत क्षेत्रीय संगठन और बड़ा जनाधार है, वह अपने राजनीतिक हिस्से पर समझौता क्यों करे?

बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शुरुआती तौर पर लगभग 24 सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रस्ताव का आधार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रदर्शन बताया जा रहा है। खास तौर पर उन सीटों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। यानी दोनों दलों के बीच शुरुआती अंतर ही 157 सीटों का है। यह अंतर बताता है कि बातचीत कितनी कठिन होने वाली है।

दरअसल, कांग्रेस की 181 सीटों की



मांग के पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। अमेठी और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में उसकी वापसी ने पार्टी के भीतर यह उम्मीद पैदा की कि विधानसभा चुनाव में भी उसे बड़ा राजनीतिक विस्तार मिल सकता है। कांग्रेस अब गठबंधन में केवल सहयोगी की भूमिका निभाने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत को फिर से स्थापित करना चाहती है। 181 सीटों की मांग इसी रणनीति का हिस्सा है।

लेकिन अखिलेश यादव के सामने भी अपनी अलग राजनीतिक मजबूरियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में महज दो सीटें आई थीं। ऐसे में सपा नेतृत्व कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक ताकत का आकलन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कर रहा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें दे दीं, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवारों, मौजूदा विधायकों और क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा।

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों वाली लगभग 22 सीटें भी शामिल बताई गई हैं। इनमें अमेठी, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। यही वह बिंदु है जहां गठबंधन की दोस्ती और राजनीतिक हित आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर दावा कर रही है, जबकि सपा अपने मौजूदा विधायकों और परंपरागत वोट बैंक वाली सीटों को छोड़ने के मूड में नहीं दिखती।

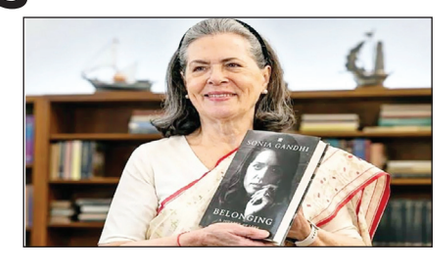
देखा जाये तो अखिलेश यादव का 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कांग्रेस को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है। संदेश यह है कि लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी का सीधा आधार नहीं बनाया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा का चुनाव अलग सामाजिक समीकरणों, स्थानीय उम्मीदवारों और बूथ स्तर के संगठन पर लड़ा जाता है। सपा मानती है कि मुस्लिम-यादव आधार और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच उसकी राजनीतिक पकड़ उसे गठबंधन में स्वाभाविक रूप से बड़ी हिस्सेदारी का हकदार बनाती है।

दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी पीछे हटने का विकल्प आसान नहीं है। यदि पार्टी 24 या उसके आसपास सीटों पर समझौता करती है, तो उसके प्रदेश संगठन में यह संदेश जा सकता है कि कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी की छोटी सहयोगी बनकर रह गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ना उसके दीर्घकालिक विस्तार की रणनीति को कमजोर कर सकता है। हालांकि 24 सीटों का प्रस्ताव अंतिम समझौता नहीं, बल्कि शुरुआती मोलभाव की स्थिति है। राहुल गांधी ने भी सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को महत्व देने की बात कही है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग पर कुछ नरमी दिखा सकती है, लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी की शर्त से पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होगा।

बहरहाल, अखिलेश यादव 24 सीटों के शुरुआती दांव से अपनी मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 181 सीटों की मांग के जरिए अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करना चाहती है। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर वर्चस्व की लड़ाई है। भाजपा के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का दावा करने वाले दोनों दलों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सत्ता के खिलाफ लड़ाई शुरू होने से पहले वे एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मुकाबले में न उलझ जाएं।

सोनिया : कुछ पर्दे उठे लेकिन रहस्य अभी बरकरार

पूनम आई. कौशिश



कल तक सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत थीं, जिनके व्यक्तित्व पर रहस्य का आवरण छाया हुआ था। वह अपनी निजता की रक्षा कुछ उसी दृढ़ता से करती थीं, मानो कोई व्यक्ति देश के गोपनीय राकों की हिफाजत कर रहा हो। लेकिन उनकी पुस्तक 'बिलांगिंग = जर्नी ऑफ लव' के प्रकाशन के बाद सोनिया के जीवन के शुरुआती दौर, इटली में बिताए दिनों, प्रेम और राजीव गांधी के साथ विवाह की कहानी के कई आत्मीय पहलू सामने आए हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से उठता है। यदि पाठकों को उम्मीद थी कि यह पुस्तक गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत के रहस्यों से पर्दा उठाएगी, सत्ता के केंद्र में रही महिला के व्यक्तित्व को करीब से समझने का अवसर देगी, उसकी राजनीतिक विरासत का निष्पक्ष आकलन करेगी अथवा भारतीय राजनीति के कुछ सबसे अंधकारमय अध्यायों की व्याख्या करेगी, तो उन्हें इन सवालों के जवाब पंक्तियों के बीच तलाशने होंगे। पुस्तक में एक महिला, उसकी भावनाओं और स्मृतियों का चित्रण तो है लेकिन राजनेता सोनिया कहां हैं? सत्ता में उनकी भूमिका का लेखा-जोखा कहां है?

अब आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है लेकिन अपने तरीके से। उनका कहना है कि यह एक निजी संस्मरण है, राजनीतिक पुस्तक नहीं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के निजी संस्मरण को सार्वजनिक जांच-पड़ताल का दस्तावेज बनाने की अपेक्षा करना भी उचित नहीं होगा। फिर भी सवाल उठता है कि यह पुस्तक सोनिया गांधी के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताती है? उस राजनेता के बारे में क्या जानकारी देती है, जो सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को बेहद संभालकर रखती रही हैं? कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वकर्त्ता रहीं सोनिया ने 2004 से 2014 तक यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 के दौरान तमाम अहम फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाई, जबकि उन्होंने कभी कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला। क्या उनका राजनीतिक इतिहास ऐसे अनेक अनसुलझे और अनुत्तरित सवालों से भरा नहीं है? क्या उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है या इतिहास का वह संस्करण प्रस्तुत किया है, जिसे वह आने वाली पीढ़ियों की स्मृति में सुरक्षित रखना चाहती हैं? क्या पारिवारिक तस्वीरों का एलबम खोलने की कीमत राजनीतिक जवाबदेही के दस्तावेज को बंद रखकर चुकाई गई है? कोई भी राजनीतिक परिवार अपनी उपलब्धियों का श्रेय तो नहीं ले सकता लेकिन अपनी विफलताओं के लिए सुविधानुसार दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहे।

क्या यह वास्तव में आत्मकथा है, विरासत को संवारने का सुनियोजित प्रयास या राजनीतिक नुकसान की भरपाई की कवायद? जिस परिवार ने भारत की राजनीतिक विरासत पर इतना बड़ा दावा किया है, उसके संदर्भ में पुस्तक में सामने आए खुलासों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वे बातें हो सकती हैं, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। जब आपातकाल कांग्रेस के लिए चुनावी त्रासदी साबित हुआ, तब संजय गांधी को इसका खलनायक बताया गया, जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी को गलत रास्ते पर डाल दिया था। जब परिवार के भीतर रिश्तों में दरार आई, तब मेनका गांधी को महत्वाकांक्षी और परेशानी खड़ी करने वाली बहू के रूप में पेश किया गया, जो घर छोड़कर चली गईं। शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी के फैसले का बचाव करते हुए सोनिया एक बीच का रास्ता अपनाती हैं। उनके अनुसार-रूढ़िवादी मुस्लिम नेतृत्व के दबाव के बावजूद राजीव ने धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। भले ही इस फैसले ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के वैचारिक दावे को चुनावी गणित तक सीमित कर दिया हो।

इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 1984 के सिख नरसंहार की जिम्मेदारी, जिसे राजीव गांधी के इस कथन-'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' के संदर्भ में देखा जाता है, सोनिया ने कथित तौर पर प्रशासनिक और नौकरशाही की विफलताओं पर डाल दी है। इसके बाद बोफोर्स घोटाला सामने आया, जो गांधी परिवार के गले की ऐसी फांस बन गया, जिससे परिवार के करीबी माने जाने वाले इतालवी कारोबारी क्वात्रोच्चि का नाम भी जुड़ गया। दशकों बाद यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में जब 2जी और कोयला घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों तथा नीतिगत निष्क्रियता ने सरकार को घेर लिया, तब संवैधानिक जवाबदेही का बोझ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आ गया, जबकि सोनिया गांधी राजनीतिक सत्ता के केंद्र में बनी रहीं। क्या यह महज संयोग था, पारिवारिक समीकरणों का परिणाम या राजनीतिक जवाबदेही से दूरी बनाए रखने की सोची-समझी रणनीति? वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से सोनिया गांधी के इंकार को त्याग और बलिदान के असाधारण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संभव है कि यह त्याग रहा हो लेकिन उन्होंने सत्ता का त्याग नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने सत्ता के संचालन का एक अधिक सुविधाजनक तरीका खोज लिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने यू.पी.ए. का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) की अध्यक्ष भी रहीं, जिसने सरकार के सामाजिक और विधायी एजेंडे को प्रभावित किया।

सोनिया गांधी ने एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत निजी प्रेम-कथा के माध्यम से दशकों के कठोर राजनीतिक फैसलों को सार्वजनिक समीक्षा से अलग रखने का प्रयास किया है। उनके निजी दुख और भावनात्मक पीड़ा की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के बावजूद आलोचकों का मानना है कि यह पुस्तक निष्पक्ष ऐतिहासिक दस्तावेज की बजाय नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का चुनिंदा बचाव अधिक प्रतीत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ संबंधों में आई कड़वाहट का इसमें उल्लेख नहीं है। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश नहीं दिए जाने की घटना भी इतिहास का हिस्सा है। इसी तरह यू.पी.ए.-2 के शासनकाल की प्रशासनिक विफलताओं पर भी पुस्तक मौन है। सोनिया गांधी कांग्रेस पर लगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों, विशेषकर बाबरी मस्जिद विवाद से निपटने के उसके तौर-तरीकों पर भी पर्याप्त चर्चा नहीं करतीं। इससे हिंदू मतदाताओं का एक वर्ग कांग्रेस से दूर हुआ और भारतीय जनता पार्टी को राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से अपनी हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने का अवसर मिला।

क्वाड: सहयोग का मंच या शक्ति-संतुलन की नई धुरी?

डॉ. प्रियंका 'सौरभ'

हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज विश्व राजनीति का ऐसा केंद्र बन चुका है, जहाँ समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक हित, सामरिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक शक्ति-संतुलन एक-दूसरे से जुड़े हैं। चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता, समुद्री विवाद, व्यापारिक निर्भरता और महत्त्वपूर्ण तकनीकों पर नियंत्रण की होड़ ने इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है। ऐसे समय में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्पक्षीय सहयोग समूह 'क्वाड' भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का महत्त्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इसका महत्त्व केवल चार देशों के आपसी सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें स्वतंत्रता, नियमों का सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और सामूहिक विकास को प्राथमिकता मिले। भारत की हिंद-प्रशांत नीति का उद्देश्य किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनकर शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में संतुलन, स्थिरता और सहयोग बनाए रखना है। क्वाड भारत को अपनी समुद्री, आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर देता है। हिंद महासागर भारत की आर्थिक जीवनरेखा है। देश का व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संपर्क समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। मलक्का जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य और हिंद महासागर के प्रमुख व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी है। इन क्षेत्रों में किसी भी तनाव, अवरोध या समुद्री असुरक्षा का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्वाड के माध्यम से समुद्री निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान, समुद्री डकैती की रोकथाम और सुरक्षित नौवहन में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। क्वाड का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन है। दक्षिण चीन सागर में विवाद, समुद्री सीमाओं को लेकर तनाव और एकतरफा गतिविधियाँ छोटे देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाती हैं। भारत ऐसी व्यवस्था का समर्थक है, जिसमें सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिले। क्वाड इस दृष्टिकोण को सामूहिक स्वर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्रीय शांति, समुद्री स्वतंत्रता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर सकता है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर भी है, लेकिन भारत की नीति टकराव के बजाय संयम और कूटनीति पर आधारित रहनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी क्वाड की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक संकटों, युद्धों और महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ सीमित देशों पर अत्यधिक निर्भर आपूर्ति व्यवस्था अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती है। औषधियों, अर्धचालकों, दुर्लभ खनिजों, ऊर्जा और तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति में विविधता लाना अब आर्थिक विवशता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बन गया है। क्वाड के सहयोग से भारत को निवेश, विनिर्माण, नई तकनीकों और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इससे भारत को केवल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन और नवाचार के विश्वसनीय केंद्र के रूप में विकसित होने में सहायता मिलेगी। तकनीकी सहयोग क्वाड की भविष्यगत शक्ति का प्रमुख आधार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल ढाँचे जैसे क्षेत्रों में साझा प्रयास भारत की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज साइबर हमले, संचार व्यवस्था में व्यवधान और समुद्र के भीतर बिछी संचार केबलों की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में सहयोग के साथ अपनी अनुसंधान क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग को विकसित करता है, तो यह साझेदारी उसके दीर्घकालीन हितों के लिए लाभकारी होगी।

महंगे सीरम को कहें अलविदा, घर पर बनाएं असरदार विटामिन सी सीरम, मिलेगी दमकती त्वचा



अगर आप भी रोजाना रात में स्किन केयर करना नहीं भूलती हैं और चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई प्रयास करती हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि महिलाएं अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए तरह-तरह के प्रोडक्ट्स फेस पर लगाती हैं। लेकिन आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक ऐसे विटामिन सी सीरम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना रात में सोने से पहले कर सकती हैं।

अगर आप इस खास सीरम को लगाती हैं, तो इससे मार्केट के महंगे सीरम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप कम पैसों में इस सीरम को बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर रहकर विटामिन सी सीरम कैसे बनाया जा सकता है।

होममेड विटामिन सी सीरम

ब्यूटी एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप घर पर एक खास विटामिन सी सीरम तैयार करना चाहती हैं, तो आप कम पैसे में इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसको बनाने का तरीका भी काफी आसान है और इसको बनाने के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होगी।

सामग्री

गुलाब जल
विटामिन सी पाउडर
विटामिन ई कैप्सूल
एलोवेरा जेल
ग्लिसरीन

ऐसे बनाएं विटामिन सी सीरम

आप घर पर आसानी से यह खास सीरम बनाकर तैयार कर सकती है। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में विटामिन सी पाउडर ले लें। अब इसमें गुलाब जल, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें विटामिन सी कैप्सूल की कुछ बूंदे डालकर इस सीरम को अच्छे से मिक्स कर लें। इस आसान तरीके से आपका होममेड सीरम बनकर तैयार हो गया है।

आप रोजाना रात में सोने से पहले इस सीरम को आपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। आप 15 दिन तक इस सीरम का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो रोजाना रात में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर सप्ताह में 3 - 4 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जब भी इसको फेस पर अप्लाई करें, तो पहले साफ पानी से चेहरे को धो लें और फिर फेस के सूखने के बाद इस सीरम को फेस पर लगाएं। इसको आप फेस के साथ-साथ गर्दन पर भी लगा सकती हैं।



घर की सब्जी को दें शाही ट्विस्ट! बस काजू-बादाम, मूंगफली से बढ़ाएं ग्रेवी का जबरदस्त स्वाद

रेस्तरां स्टाइल में हम सभी टेस्टी सब्जी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मिस्टेक जरुर हो जाती है। अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान देना काफी जरुरी है। घर में चाहे कितना भी टेस्टी खाना बना लें, लेकिन बच्चे फिर कमी निकाल देते हैं। ऐसे में हर महिलाओं को इन टिप्स का जरुर पता होना चाहिए। अगर आप मेवों की मदद से सब्जी में इस्तेमाल करके लाजवाब खाना बना सकते हैं। मेवे सब्जियों के स्वाद को दोगुना कर देते हैं। यह सब्जी में स्वाद तो बढ़ा ही देते हैं और यह काफी हेल्दी भी होती है। आइए आपको बताते हैं मेवे से सब्जी की क्रीम को गाढ़ा और क्रीमी से बनाएं।

मेवे से सब्जी को गाढ़ा और क्रीमी कैसे बनाएं

- इसके लिए आप काजू या बादाम को गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। अब इसे पानी से निकालकर थोड़ा दूध या पानी डालकर एक चिकना पेस्ट बना लें। फिर आप इसे सब्जी की ग्रेवी में डालें। इससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी, क्रीमी और रयादिष्ट बनेगी। इसका यूज आप शाही पनीर, कोफ्ता और मलाई कोफ्ता जैसी सब्जियों में कर सकते हैं। आप बादाम, काजू या मूंगफली को हल्का भूनकर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सब्जी तैयार होने के बाद ऊपर से इन टुकड़ों को डालें। सब्जी तैयार होने के बाद ऊपर से आप इन टुकड़ों को डालें। ऐसा करने से सब्जी में कुरकुरापन और रयादिष्ट मेवो वाला फ्लेवर आएगा। सूखी सब्जियों के लिए भी यह तरीका बेस्ट है।

- भुनी हुई मूंगफली का पेस्ट बनाकर ग्रेवी में डाल सकते हैं। इससे आपकी ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। आप तिल को पीसकर उसका पेस्ट भी ग्रेवी में मिला सकती हैं। इससे ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाता है।

- बादाम या काजू को पीसकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आप मसाले की तरह किसी भी सब्जी की ग्रेवी में डाल दीजिए। प्याज की जगह दही और मूंगफली का पेस्ट बनाकर ग्रेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रेवी गाढ़ी होने के साथ ही उसका स्वाद भी काफी कमाल लगेगा।

सर्दी-जुकाम से राहत के लिए अपनाएं दादी-नानी का नुस्खा, बेसन का शीरा देगा तुरंत आराम।



बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी-जुकाम की शिकायत हो जाती है। बच्चों की इम्युनिटी कमजोर होने के कारण खांसी-जुकाम की समस्याएं बन जाती है। यदि आपके बच्चे को मौसम के बदलने से सर्दी-जुकाम से परेशान हो गए है, तो इसे दवाओं की जगह आप एक बार बेसन का शीरा बनाकर जरुर पिलाएं। यह एक ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी है, जो मौसम बदलने के बाद बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बीमारी से लड़ने में मदद करती है। बेसन शीरा स्वाद के साथ ही हेल्थ के लिए काफ बढ़िया है। इसके सेवन से सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या जल्द ठीक हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी बेसन का शीरा।

बेसन का शीरा बनाने के लिए सामग्री

- 3 बड़े चम्मच बेसन
- 1 बड़ा चम्मच देसी घी
- 2 छोटी चम्मच चीनी/गुड़
- डेढ़ कप दूध
- कुटी हुई इलायची
- 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन
- कटे हुए बादाम
- कुटी हुई काली मिर्च
- हरा धनिया
- 1 चुटकी हल्दी

बेसन का शीरा बनाने का तरीका

बेसन का शीरा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कड़ाही लें और गैस पर चढ़ाकर गर्म करें। अब इसमें घी डालें और बेसन को लो फ्लेम पर भूने जब तक इसका रंग हल्का भूरा ना हो जाए। बेसन को अच्छे से भून जाने के बाद इसमें खुशबू आने लगेगी। अब इसमें बेसन इलायची, गुड़, कटे हुए बादाम, कुटी हुई काली मिर्च, अजवाइन और हल्दी डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिला लीजिए। इसके बाद आप इसमें दूध डालते हुए सभी चीजों को करछी से लगातार चलाते हुए मिलाएं, वरना बेसन में गांठें पड़ जाएगी। बेसन में पड़ी गांठे शीरा का स्वाद बिगड़ सकती हैं। इसके बाद आप दूध को 5 मिनट तक अच्छे से उबालें। इसके बाद बेसन के शीरे में कटा हुआ ताजा हरा धनिया डाल दें। यह लीजिए टेस्टी गर्मागर्म बेसन का शीरा तैयार है। बेसन का शीरा पीने के बाद बच्चों को खुली हवा में बाहर ना भेजें। क्योंकि ऐसा करने से इसका असर कम हो जाता है। बेसन का शीरा पीने के बाद बच्चे सोने दें।

बासी पोहा हो गया सख्त तो अपनाइए ये आसान नुस्खा, मिलेगा वही पुराने जैसा स्वाद

नाश्ते में पोहा खाना आखिरकार किसे अच्छा नहीं लगता। सुबह अक्सर चाय के साथ पोहा खाने में एक अलग ही मजा आता है। लेकिन पोहा केवल तभी अच्छा लगता है, जब उसे बनाकर गरमा-गरम सर्व किया जाए। अगर उसे बाद में खाया जाता है तो वह थोड़ा सख्त और सूखा-सूखा महसूस होता है। इतना ही नहीं, उसका वो टेक्सचर भी गायब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे खाने का मन ही नहीं करता है। हालांकि, अगर आप ऐसे में उसे फेंकने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जादू करने पर बासी पोहा को फिर से नरम, टेस्टी और फ्रेश बना सकते हैं।

वास्तव में, पोहा उन आसान डिशेज में से है, जिसे अगर सही ट्रिक से दोबारा गरम किया जाए तो उसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही पहले जैसा हो जाता है। तब आपको उसे खाते समय ऐसा महसूस होता है, जैसा कि इसे अभी-अभी गरमागरम बनाया गया हो। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही आसान टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके बासी पोहे को फिर से टेस्टी बनाने में मदद करेंगे-

थोड़ा पानी छिड़कें

यह एक आसान तरीका है बासी पोहा को फिर से फ्रेश करने का। इसके लिए सबसे पहले पोहे को एक कटोरे या कड़ाही में डालिए और उस पर 2-3 चम्मच पानी हल्के से छिड़किए। अब इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए। दरअसल, पोहा इसलिए सूख जाता है क्योंकि उसमें से नमी निकल जाती है। थोड़ा पानी और भाप उसे विधिवत किए बिना दोबारा नरम बना देते हैं।

थोड़ा तेल या घी डालकर दोबारा गरम करें

एक पैन में 1 चम्मच तेल या घी गरम करें। चाहें तो उसमें थोड़े राई के दाने, करी पत्ता या एक चुटकी हल्दी डालें। अब उसमें बासी पोहा डालकर 1-2 मिनट तक चलाइए। जब आप पोहे को हल्का सा भूनते हैं तो इससे पोहे की खुशबू और स्वाद दोनों ताजा हो जाते हैं। तेल हर दाने को कोट कर देता है जिससे पोहा दोबारा चिपकता नहीं है।

आजमाएं माइक्रोवेव ट्रिक

अगर आपके पास समय कम हो तो माइक्रोवेव की इस ट्रिक को भी आजमाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पोहे पर थोड़ा पानी छिड़कें, फिर उस पर गीला टिशू पेपर या माइक्रोवेव ढक्कन रखकर 30-40 सेकंड के लिए गरम करें। गीला टिशू भाप को अंदर रोकता है, जिससे पोहा बराबर गरम होता है और सूखता नहीं है।





किचन के इन 3 मसालों से पाएं मुंह की बदबू से छुटकारा, बनाएं नेचुरल माउथवॉश!

हर भारतीय के किचन में पाए जाने वाले ये मसाले केवल खाना का स्वाद ही नहीं, मुंह की दुर्गंध और बैक्टीरिया को दूर भगा देते हैं। आपकी रसोई में रखें इन 3 मसालों से तैयार करें नैचुरल माउथवॉश। मुंह की दुर्गंध, मसूड़ों की सूजन और बैक्टीरिया संक्रमण की समस्या से परेशान हो गए हैं, तो यह लेख आपके लिए है। वैसे तो बाजार में कई सारे माउथवॉश मिलते हैं लेकिन इनमें केमिकल्स और अल्कोहल की मात्रा होती है। यह अस्थायी ताजगी तो पहुंचता है लेकिन लंबे समय तक दांतों और मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। इसी कारण आप अपने घर पर ही इन 3 मसालों से नैचुरल माउथवॉश बना सकते हैं। लौंग, चक्र फूल और दालचीनी से बना यह घरेलू माउथवॉश आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। यह माउथवॉश आपके मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। आइए आपको बताते है इसे कैसे बनाएं।

माउथवॉश बनाने की विधि

सामग्री

- 4-5 लौंग
- 2 चक्र फूल
- 1 दालचीनी का टुकड़ा
- 1 कप पानी

इसे बनाने का तरीका

- सबसे पहले आप एक पैन में पानी डालें। फिर इसमें लौंग, दालचीनी और चक्र फूल को डालें।

- फिर आप इसे 7-8 मिनट तक उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक इसका रंग हल्का भूरा न लग जाए।

- जब यह पानी ठंडा हो जाए, तो इसे कांच की बोतल में भरकर रख दें।

- इसे घरेलू माउथवॉश से आप दिन में 1 या 2 बार कुल्ला जरुर करें।

घरेलू माउथवॉश इस्तेमाल करने के फायदे

- मुंह की दुर्गंध दूर करता है और सांसों को लंबे समय तक तरोताजा रखता है।

- इसमें एंटीबैक्टीरियल के गुण होते हैं, जो कि मुंह में बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।

- मसूड़ों की सूजन को कम करता है और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है।

- यह एक प्रकार से 100% प्राकृतिक और केमिकल-फ्री जो दांतों के एनामेल को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी, बलेन शाह ने अयोध्या -जनकपुर ट्रेन का शुभारंभ किया



नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्विपक्षीय बातचीत के बाद नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सेवा की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा-पार कनेक्टिविटी और लोगों के आपसी संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। अयोध्या से सरयू-कमला एक्सप्रेस में सवार होने जा रहे एक यात्री ने अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि इससे इन दोनों धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। यात्री ने मीडिया को बताया इसे लेकर काफी उत्साह है। कई श्रद्धालु इसमें सफर करेंगे। यह ट्रेन उन दो जगहों को जोड़ती है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ी हैं।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा



लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने अपने सांसदों, विधायकों और एमएलसी को 5 दिसंबर तक पूरे राज्य में चौपाल (जनसंपर्क बैठकें) आयोजित करने का लक्ष्य दिया है। विधानसभा चुनाव संभवत: अगले साल फरवरी या मार्च में होंगे। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान, बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने पार्टी विधायकों को निर्देश दिया कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में 50-50 चौपाल आयोजित करें। राज्य के सभी बीजेपी सांसदों से भी कहा गया है कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में ऐसी 10-10 बैठकें आयोजित करें। पार्टी ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना भी बनाई है, जहां उसका कोई विधायक नहीं है या जहां संगठनात्मक रूप से पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर है। इन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के लिए आयोजित होने वाली बैठकों की जिम्मेदारी बीजेपी के एमएलसी संभालेंगे।

ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट



नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आठ साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वह अदालत के सामने पेश नहीं हुए। साकेत कोर्ट ने यह कदम तब उठाया जब 17 अक्टूबर को जारी किया गया जमानती वारंट राठी तक नहीं पहुंचाया जा सका। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।यह मानहानि का मामला विकास सांकृत्यायन (जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है) ने दायर किया था। यह मामला मई 2018 में राठी द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में, राठी ने कथित तौर पर दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेल ने उन्हें बदनाम करने के लिए पांडे को रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस वीडियो को राठी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया था और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे रीट्वीट किया था।

टीएमसी सांसद अभिषेक को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत



कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में दर्ज छह आपराधिक मामलों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इस साल मई से बनर्जी के खिलाफ दर्ज छह मामलों के संबंध में उनकी ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को मिली यह राहत 26 फरवरी 2027 तक या अदालत के अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने इनमें से तीन मामलों में 25 अगस्त को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिसके आधार पर बनर्जी को राहत की अवधि बढ़ाने से इनकार किया जाए।

अस्तित्व बचाने के लिए ममता बनर्जी और वाम दलों की गठबंधन



कोलकाता। राज्य कैबिनेट मंत्री शरदवत मुखर्जी ने सोमवार को वाम दलों और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में मुखर्जी ने कहा कि वाम दल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा, ये पार्टियां जिस गठबंधन को बनाने की कोशिश कर रही हैं और जिसे लेकर इतनी चिंतित हैं, उसका मकसद देश का विकास करना नहीं है। यह केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किया गया गठबंधन है। वाम दल खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वे अपने छोटे-छोटे पार्टी कार्यालय भी नहीं चला पा रहे हैं। फिलहाल देश के किसी भी हिस्से पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, और मुझे लगता है कि वे बस किसी तरह राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

नेपाल के बिना हमारे राम और धाम अधूरे

24000 करोड़ नेपाली रुपये की मदद देगा भारत



नईदिल्ली। नई दिल्ली में भारत-नेपाल संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए बालेन्द्र शाह का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था, तब हमें उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की एक झलक मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत-नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति और लोगों के बीच गहरे जुड़ाव से बंधे हैं। भगवान राम और माता सीता हमारी साझा सभ्यता और आस्था के प्रतीक हैं।

अब, हमारी आमने-सामने की बातचीत के दौरान, मुझे नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनका स्पष्ट दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता महसूस हुई। कुछ महीने पहले जब बालेन्द्र शाह ने विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में ह को संबोधित किया था, तब हमें उनकी दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक दिखाई दी थी। और आज पिछले कुछ घंटों की बातचीत में मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल संबंधों के लिए उनके स्पष्ट विजन और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। इस वर्ष नेपाल की जनता ने जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वह नेपाल की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है। भारत एक सशक्त और समृद्ध नेपाल की विकास यात्रा में हमेशा सहभागी रहा है। इसी भावना से आज हमने अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में हुई जान-माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया और देश के पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालिक विकास में मदद के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपयों के विकास सहयोग पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने सोमवार, 23 नवंबर को भारत में अयोध्या धाम को नेपाल में जनकपुर धाम से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत कांडला और पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच देगा। उन्होंने कहा कि इससे नेपाल के आर्थिक विकास और निवेश को गति मिलेगी। ऊर्जा सहयोग पर पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल की नदियों में स्वच्छ बिजली पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। आज लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है और अरुण-3 परियोजना को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण का उद्घाटन और नेपाल में जैपा पेट्रोलियम टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। इससे ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति मजबूत होगी।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण और भारत में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्तों की नींव आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और सद्भावना पर टिकी है। दोनों देशों के लोगों के बीच गहरा जुड़ाव इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। बालेन शाह ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध हिमालय की तरह मजबूत और समुद्र की तरह विशाल हैं।

सीट बंटवारे पर सपा-कांग्रेस में मंथन दिल्ली में जुटे दोनों दलों के नेता



नई दिल्ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सीट-बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इसमें दोनों दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई। गठबंधन का लक्ष्य दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाना है। सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा,बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। एक दूसरे की बात को सुना और हम जल्द ही इस गठबंधन को आखिरी तक पूरा करके आपको जल्द बताएंगे। 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। दूसरी बैठक आज होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, दोनों (कांग्रेस और सपा) की सहमति है और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दोनों मिलकर गठबंधन करेंगे, यह लगभग तय है और सम्मानपूर्ण तरीके से समझौता होगा। बहुत जल्द (समझौता) होगा।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा, कितने नंबरों पर बात हुई, इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। 2-4 दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा... जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, गठबंधन मजबूत है, विश्वसनीयता है तो लंबी चर्चा करने की जरूरत क्या है?... शुरुआत की जो बैठक हुई है, वो बहुत ही सकारात्मक और विश्वास के साथ हुई है। इस गठबंधन में दोनों के बीच में कोई संशय नहीं है। आज फिर बैठक होगी और 2-4 दिनों में सब चीज तय हो जाएंगी।

कांग्रेस की ओर से सांसद प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख आराधना मिश्रा, राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव, लोकसभा सांसद इकरा हसन, राज्यसभा सांसद राजीव राय और राज्य अध्यक्ष श्याम लाल पाल मौजूद रहे। प्रमोद तिवारी ने एएनआई को बताया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष निर्वाचन क्षेत्रों और संभावित उम्मीदवारों का अपना-अपना आकलन प्रस्तुत किया।

तिवारी ने बैठक के स्थान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह आवास पार्टी द्वारा उन्हें आवंटित किया गया है। सीट-बंटवारे की बैठक अलग-अलग दिनों में अलग-अलग स्थानों पर हो सकती है। कांग्रेस द्वारा पहले 181 सीटों की सूची सौंपने की खबरों पर तिवारी ने टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह बातचीत करने वाली समिति के सदस्य नहीं हैं। प्रमोद तिवारी ने जोर दिया कि जीतने की क्षमता सीट-बंटवारे की व्यवस्था में एक प्रमुख विचार होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में जीतने की क्षमता सबसे बड़ा कारक होती है। तिवारी ने भाजपा के राधे राधे कमल खिला दे नारे पर कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा।

कंपनियों पर पीएम मोदी की बात का शशि थरूर ने किया समर्थन



तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस आलोचना का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को आड़े हाथों लिया था। मोदी ने कहा था कि टैक्स में छूट मिलने के बावजूद, ये कंपनियां न तो नौकरियां पैदा कर पाईं और न ही वेतन बढ़ा पाईं। थरूर ने कहा कि देश में रोजगार की स्थिति, खासकर ग्रेजुएट्स के लिए, बेहद खराब बनी हुई है। थरूर ने सरकार के रेगुलेटरी ढांचे की भी आलोचना की और कहा कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। इस दौरान उन्होंने मोदी के न खाऊंगा, न खाने दूंगा वाले नारे पर भी तंज कसा। केरल के तिरुवनंतपुरम में बोलते हुए, थरूर ने कहा कि टैक्स में राहत पाने के बाद भी कंपनियों द्वारा अपने वादे पूरे न कर पाने को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी, देश की आर्थिक स्थिति की सच्चाई को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह एक सच्चाई है। हो सकता है कि कॉरपोरेट जगत के पास इसके बचाव में अपनी कोई दलील हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनका तर्क यह है कि सरकार ने टैक्स इसलिए कम किए थे ताकि कंपनियों को ज्यादा निवेश करने, अधिक नौकरियां पैदा करने और वेतन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, लेकिन कंपनियों ने अपनी तरफ से किए गए वादे को पूरा नहीं किया है।

थरूर ने नौकरी चाहने वालों, खासकर कॉलेज से स्नातक करने वालों के सामने आ रही मुश्किलों पर प्रकाश डाला और कहा कि रोज़गार की स्थिति पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा लोग हमें बताते हैं कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ढ्ढङ्ख ग्रेजुएट को प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। मेरा मतलब है कि पहले ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थीं, जिससे पता चलता है कि रोज़गार का माहौल, खासकर कॉलेज से स्नातक करने वालों के लिए, काफी निराशाजनक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी को लेकर सरकार और कॉर्पोरेट जगत के बीच चल रही बहस पर करीब से नजर रखी जानी चाहिए। थरूर ने कहा अगर प्रधानमंत्री कंपनियों की ओर उंगली उठा रहे हैं और कंपनियां सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं, तो यह ऐसी चीज है जिस पर हम नजर रख सकते हैं। हमारा मानना ??है कि सरकार कुछ चीजें बेहतर तरीके से कर सकती है।

थरूर ने सरकार के रेगुलेटरी ढांचे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के दावों के बावजूद, कारोबारियों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे नियमों को आसान बना सकते थे लेकिन असल में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन कारोबारियों से उनकी बात हुई, उनका मानना है कि हालात और खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा मुझे यह कहते हुए अफ़सोस हो रहा है कि जिन भी कारोबारियों से मेरी बात हुई, उनके अनुसार भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ



वेलिंगटन। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच चल रही सीरीज़ का पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोनों टीमें 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में आमने-सामने थीं। पाँच दिनों के कड़े संघर्ष के बाद, जब भारत दूसरी पारी में न्यूज़ीलैंड को ऑल आउट नहीं कर सका, तो यह मुक़ाबला ड्रॉ हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रॉ के बाद, भारत के लिए डब्ल्यूटीसी फ़ाइनल में जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया है। अगर भारत को डब्ल्यूटीसी के फ़ाइनल में पहुँचना है, तो उन्हें अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे। वेलिंगटन में हुए इस ड्रॉ के कारण, डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में भारत चौथे स्थान पर बना हुआ है। हालाँकि भारत स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर तो है, लेकिन उनका पीसीटी गिरकर 50 हो गया है, जिससे फ़ाइनल में पहुँचने की उनकी उम्मीदों को और झटका लगा है। वहीं, न्यूज़ीलैंड की टीम टॉप-2 से बाहर हो गई है और उनका पीसीटी गिरकर 66.66 पर आ गया है। इसके अलावा, 75 के पीसीटी के साथ दक्षिण अफ़्रीका स्टैंडिंग में सबसे ऊपर बना हुआ है।

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले गए मैच की बात करें तो, पहली पारी में 368 रन खाने के बाद, भारत ने बल्लेबाज़ी करते हुए 720 रन बनाए और 352 रनों की बढ़त के साथ पारी घोषित कर दी। इस दौरान केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतक लगाए, जबकि शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल और अंशुल कंबोज ने भी अपनी बल्लेबाज़ी से प्रभावित किया।

दूसरी पारी में जब न्यूज़ीलैंड बल्लेबाज़ी करने उतरी, तो उसने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल की जोड़ी ने टीम को संभाले रखा। पांचवें दिन का खेल खत्म होने तक न्यूज़ीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए थे। इसके बाद दोनों टीमों ने हाथ मिलाया और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम

मुंबई। दुनियाभर के शेयर बाजारों में जारी कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत में शानदार तेजी दिखाने वाले घरेलू शेयर बाजार में अचानक बिकवाली हावी हो गई। सेंसेक्स 1,483.72 अंक यानी 1.77 फीसदी गिरकर 82,435.99 पर आ गया। वहीं निफ्टी 50 में 450.95 अंक यानी 1.75 फीसदी की गिरावट आई और यह 25,349.65 पर बंद हुआ। बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और मेटल सेक्टर से आया। निफ्टी मेटल में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2 फीसदी से अधिक टूटे। दूसरी ओर आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी आईटी डेढ़ फीसदी से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य प्रमुख इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के कारण बाजार में तेज उतार-चढ़ाव रहा।

विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी में सेबी

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अतिरिक्त जानकारी देने से जुड़े नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। ये नियम तीन साल पहले अगस्त 2023 में लागू किए गए थे। सेबी का मानना है कि मौजूदा नियम दूसरे बड़े बाजारों के मुकाबले ज्यादा सख्त हैं। इनकी वजह से विदेशी निवेशकों को काफी कागजी कार्रवाई और जानकारी जुटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नए प्रस्ताव का मकसद इस बोझ को कम करना और भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस प्रस्ताव के बाद बाजार की पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नियम आसान होने से विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी।

त्योहारी सीजन में वाहनों की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर

नईदिल्ली। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री इस साल 42 दिन के त्योहारी सत्र के दौरान सालाना आधार पर 2.21 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 55.25 लाख इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल जीएसटी 2.0 के कारण मांग बढ़ने से ऊंचे आधार के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने सोमवार को यह जानकारी दी। फाडा के अनुसार 2026 में 42 दिन की त्योहारी अवधि के दौरान वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 55,25,490 इकाई रही, जो समान अवधि के लिए अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वर्ष 2024 के त्योहारी सत्र की तुलना में वाहनों की खुदरा बिक्री में 23.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने के बाद मांग की निरंतर रफ्तार को दर्शाती है। दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 43,13,276 इकाई हो गई।

कर्नाटक में 10 लाख वाहन उत्पादन का लक्ष्य

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने सोमवार को टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन को राज्य में अपने विनिर्माण परिचालन के विस्तार के लिए सरकार की ओर से पूरा समर्थन और सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया। जापानी वाहन विनिर्माता कंपनी निकट भविष्य में अपनी वाहन उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि जापान स्थित टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के मोटोमाची संयंत्र में कंपनी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री शिवकुमार और भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में टोयोटा के विनिर्माण को बढ़ावा देने, उत्पादन बढ़ाने और आवागमन के नए समाधान तलाशने पर चर्चा की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारतीय इकोनॉमी की तारीफ के मायने

डॉ. हिदायत अहमद खान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हैं और भारत की करीब सात प्रतिशत विकास दर को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए उदाहरण बताते हैं, तो इसे केवल भारत के प्रति उनके बदले हुए नजरिये के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उनकी इस टिप्पणी के पीछे अमेरिकी घरेलू राजनीति, आर्थिक नीतियों और फेडरल रिजर्व के साथ जारी टकराव की पृष्ठभूमि भी है। सवाल यह है कि जिस भारत पर उनके प्रशासन ने टैरिफ संबंधी दबाव बढ़ाया, जिसके नागरिकों के लिए वीजा नीतियां सख्त की गईं, उसी भारत की आर्थिक व्यवस्था अचानक उन्हें इतनी आकर्षक क्यों दिखाई देने लगी? ट्रंप की इस बात में दम है कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी सात प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसके मुकाबले उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास-दर का जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो विकास दर 14, 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में काम करता है। ट्रंप का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सरकारी कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत करने के लिए ब्याज दरें कम होनी चाहिए। दरअसल, ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करे, ताकि कारोबार, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिले। दूसरी ओर फेडरल रिजर्व का प्रमुख दायित्व महंगाई को नियंत्रित रखना और रोजगार के स्तर को संतुलित बनाए रखना है। यही वजह है कि वह केवल राष्ट्रपति की इच्छा



के अनुरूप ब्याज दरों में बदलाव नहीं कर सकता। मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का उद्देश्य भी यही है कि आर्थिक फैसले राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हों।

ट्रंप की टिप्पणी के समय अमेरिका में महंगाई का दबाव भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) आधारित महंगाई दर 3.6 प्रतिशत और कोर पीसीई महंगाई दर 3.1 प्रतिशत थी, जबकि फेड का दीर्घकालिक लक्ष्य दो प्रतिशत है। ऐसे में ब्याज दरों में जल्द और बड़ी कटौती महंगाई को फिर बढ़ाने का जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए ट्रंप का यह दावा कि कम ब्याज दरों से अमेरिकी विकास दर सीधे 15 या 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, एक राजनीतिक और आर्थिक अनुमान है, कोई स्थापित आर्थिक निष्कर्ष नहीं। ब्याज दरें विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन उत्पादकता, निवेश, रोजगार, मांग और वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। भारत की तारीफ को भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी समझना होगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में टैरिफ को लेकर तनाव पैदा हुआ। अमेरिकी नीतियों का असर भारतीय निर्यातकों और कारोबारियों की योजनाओं पर पड़ा। वीजा नियमों में सख्ती ने भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के सामने भी अनिश्चितता बढ़ाई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की व्यक्तिगत निकटता और उनकी तारीफ के बयान लगातार चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी को टफ मैन कहना और अब भारतीय अर्थव्यवस्था को उदाहरण बनाना इसी सिलसिले का हिस्सा है। लेकिन कूटनीति में व्यक्तिगत प्रशंसा और नीतिगत सहयोग दो अलग-अलग बातें हैं। नेताओं के बीच मित्रता के सार्वजनिक प्रदर्शन से व्यापारिक बाधाएं अपने आप समाप्त नहीं होतीं। भारत के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिकी बाजार तक पहुंच, निर्यात पर शुल्क, तकनीकी सहयोग, निवेश और भारतीय पेशेवरों के वीजा जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति हो। इसी तरह अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार, निवेश का अवसर और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के आर्थिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए आपसी मतभेदों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता।

शेयर बाजारों में अनिश्चितता और सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी वैश्विक आर्थिक माहौल की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं।

मुख्यमंत्री साय धनोरा में आयोजित भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती कलार महोत्सव में हुए शामिल

भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के आदर्श न्याय, धर्मरक्षा और लोककल्याण की प्रेरणा देते हैं : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कोण्डागांव जिले के ग्राम धनोरा में आयोजित 'राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती कलार महोत्सव' में शामिल हुए। उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलार समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता की सराहना करते हुए कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का जीवन न्याय, धर्मरक्षा और लोककल्याण के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। उनके आदर्श हमें समाज की सेवा और जनहित के कार्यों के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग की उन्नति में ही प्रदेश की समृद्धि निहित है और राज्य सरकार इसी भावना के साथ सभी वर्गों के कल्याण तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महोत्सव में उपस्थित समाजजनों को भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलार समाज का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। सातवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक लगभग एक हजार वर्षों तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में कलचुरी वंश का वैभवशाली शासन रहा। इस गौरवशाली विरासत को संजोते हुए कलार समाज आज शिक्षा, कृषि, व्यापार, व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने समाज की एकजुटता, परिश्रम और सामाजिक समरसता की भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि संगठित और जागरूक समाज ही प्रदेश की प्रगति को नई दिशा देता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ हो चुका है। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है और चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है। प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 55 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब विकास की सुविधाएं पहुंच रही हैं और स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।



ट्रेन ऑन डिमांडः जहां मांग, वहां गाड़ी-एसईसीआर में दो साल में चलीं करीब 1,000 टीओडी गाड़ियाँ

त्योहारों में कन्फर्म टिकट का टेंशन खत्म

रायपुर। भारतीय रेल यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी सेवाओं को निरंतर अधिक लचीला और यात्री-केंद्रित बना रही है। इसी दिशा में ट्रेन ऑन डिमांड (टीओडी), अर्थात माँग आधारित गाड़ियाँ, एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। त्योहारों, छुट्टियों, मेलों और विशेष अवसरों पर जब किसी मार्ग पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, तब टीओडी के माध्यम से उसी मार्ग पर, उसी समय अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाकर यात्रियों को राहत दी जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दो वर्षों में लगभग 1,000 टीओडी गाड़ियाँ चलाई गई हैं।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की माँग पर निरंतर नज़र रखते हुए उन्हें बेहतर, सुविधाजनक और समय पर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। ट्रेन ऑन डिमांड ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नियमित समय-सारणी से अलग, यात्रियों की वास्तविक माँग के आधार पर चलाई जाती हैं। नियमित गाड़ियाँ पूरे वर्ष एक निश्चित समय-सारणी पर चलती हैं, जबकि टीओडी किसी विशेष मार्ग पर, किसी विशेष अवधि में बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए अधिसूचित की जाती हैं। जैसे ही किसी मार्ग पर माँग बढ़ने के संकेत मिलते हैं, रेलवे उस मार्ग के लिए अतिरिक्त गाड़ी की योजना बनाकर उसे अधिसूचित करती है और यात्री उसमें सामान्य गाड़ियों की तरह आरक्षण करा सकते हैं। माँग सामान्य होने पर ये गाड़ियाँ नहीं चलाई जातीं। देश के कई मार्गों पर वर्ष भर यात्रियों की संख्या एक जैसी नहीं रहती। दीपावली, छठ, होली, गर्मी की छुट्टियों या बड़े मेलों के समय कुछ मार्गों पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जबकि वर्ष के अन्य दिनों में वही मार्ग सामान्य रहते हैं। ऐसे समय में नियमित गाड़ियों में लंबी प्रतीक्षा सूची बन जाती है और बहुत से यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन ऑन डिमांड की अवधारणा प्रारंभ की, ताकि जहाँ और जब माँग हो, वहीं और तभी अतिरिक्त गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। आज लगभग 89 प्रतिशत आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। इससे रेलवे के पास हर मार्ग, हर गाड़ी और हर तिथि के लिए यात्रियों की माँग के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध रहते हैं। इन आँकड़ों के विश्लेषण से यह आसानी से पता चल जाता है कि किस मार्ग पर, किन तिथियों में और कितनी अधिक माँग है। इसी आधार पर टीओडी अधिसूचित की जाती है।



पूर्व सांसद नंदकुमार साय हुए चोटिल, गृह ग्राम से हेलिकॉप्टर में साथ लेकर आए मुख्यमंत्री



रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर में अपने साथ रायपुर लेकर आए है। मुख्यमंत्री साय ने हैलीपेड पर सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दो दिन पहले नंदकुमार साय फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके पैर में चोट आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जशपुर प्रवास के दौरान उनके निवास के समीप ही एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला था। इस दौरान वे रात में नंदकुमार साय के निवास पहुंचकर उनसे मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पैर में चोट के कारण नंदकुमार साय को चलने-फिरने में तकलीफ हो रही थी। सोमवार को उन्हें रायपुर आना ही था, इसलिए नंदकुमार साय को भी अपने साथ हेलीकाप्टर से रायपुर ले आए, ताकि उन्हें यात्रा में असुविधा न हो और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

स्टेट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर अवॉर्ड्स : प्रदेश की डिजिटल प्रतिभाओं को मिलेगा सम्मान

16 मुख्य अवॉर्ड और 46 उपश्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, कला, पर्यटन तथा विरासत को डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 25 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, रायपुर में आयोजित होगा। इस आयोजन का संदेश है—अब हर स्क्रीन पर छाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित1 ष्टत्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित इस समारोह में प्रदेशभर के यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, फिल्ममेकर्स, फोटोग्राफर्स, ब्लॉगर्स, कलाकारों और स्टोरीटेलर्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी क्रिएटर्स से संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में नवाचार करने वाली प्रतिभाओं को पहचान देने के साथ ही प्रदेश में क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। समारोह में 16 मुख्य अवॉर्ड और 46 उपश्रेणियों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया जाएगा।

विजेताओं को मिलेगी 10 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि

विजेताओं को कुल 10 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार श्रेणियों में लाइफस्टाइल, फूड एंड फैशन, कल्चर, हेरिटेज एंड टूरिज्म, क्रिएटिव, कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट तथा ट्राइबल वॉइस सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड के 6 विजेता होंगे शामिल

समारोह में नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड के छह विजेता क्रिएटर्स और प्रसिद्ध आरजे शरत विशेष रूप से शामिल होंगे। जाने-माने डिजिटल क्रिएटर राज शमानी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता क्रिएटर्स के साथ कार्यशालाएं, विशेषज्ञ सत्र और नेटवर्किंग गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

लोधेशवरधाम में सैकड़ो की संख्या में विवाह योग्य युवक-युवती ने दिया अपना परिचय

रायपुर। लोधी क्षत्रिय समाज रायपुर के तत्वावधान में रविवार लोधी क्षत्रिय समाज रायपुर का वार्षिक सम्मेलन, युवक- युवती परिचय सम्मेलन, दीपावली मिलन समारोह एवं स्मारिका का विमोचन कुम्हारी टोल प्लाजा के पास स्थित लोधेश्वरधाम में बडे ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विवाह योग्य युवक-युवतियों ने अपने लिए जीवन साथी की तलाश में अपना परिचय दिया। इस अवसर पर पिछोर ग्वालियर मध्यप्रदेश चंबल के टाईगर एवं लोधी समाज के मसीहा प्रीतम सिंह लोधी, मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि लोधी समाज का बडा इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में समाज का अच्छा जनाधार है। युवाओं को समाज से जुडकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशा से मुक्त रहने की अपील की है।



अध्ययन ने पहली वर्षगांठ पर 'द पीपल पोस्ट' का किया शुभारंभ

रायपुर। रायपुर के ओपन राइटिंग और साहित्यिक समुदाय 'अध्ययन' ने 22 नवंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। यह अवसर 2 नवंबर 2025 को समुदाय की स्थापना के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सतप्रिया कौर द्वारा शुरू की गई इस पहल की शुरुआत एक छोटे-से विचार के रूप में हुई थी, जो आज लोगों के एक ऐसे साझा मंच में बदल चुकी है, जहां वे एक साथ आकर लेखन को समझते हैं। रचनात्मकता को तलाशते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। रायपुर में आयोजित होने वाले इसके निःशुल्क साप्ताहिक सत्रों में कविता, साहित्य, कहानी कहने से लेकर संगीत, कला और रोजमर्रा के अनुभवों तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यह मंच हर पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत करता है, फिर चाहे वे स्वयं को लेखक मानते हों या नहीं। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, अलग-अलग दृष्टिकोणों को साझा करना और शब्दों के माध्यम से आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इस वर्षगांठ समारोह के अवसर पर 'द पीपल पोस्ट' नामक न्यूज़लेटर का भी शुभारंभ किया गया। सतप्रिया कौर और वाई. जाह्नवी द्वारा शुरू किया गया।



राज्यपाल ने सरस्वती महाविद्यालय को दिए 10 कंप्यूटर और प्रिंटर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने सोमवार को लोकभवन में सरस्वती महाविद्यालय, बिलासपुर को अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदान किए। इस पहल का उद्देश्य महाविद्यालय में शैक्षणिक और तकनीकी सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना है। श्री डेका ने कहा कि महाविद्यालय की डिजिटल व तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना और विद्यार्थियों के अध्ययन को अधिक सुगम व आधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदाए किए जा रहे हैं। यह 10 कंप्यूटर और प्रिंटर राज्यपाल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रदान किए हैं। इस अवसर पर सरस्वती महाविद्यालय के अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सदस्य सर्वश्री बृजेंद्र शुक्ला, विवेक सक्सेना, लक्ष्मण राव मागर और बद्रीनाथ केसरवानी सहित महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।



बालमुमुक्षु निपुण बैद को समर्पित भव्य स्नात्र पूजा के साथ संपन्न हुआ संयम संग्रामोत्सव

रायपुर। आत्मशुद्धि, तप आराधना और संयम साधना के भावों से सुसज्जित तीन दिवसीय 'संयम संग्रामोत्सव' का समापन सोमवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन सिद्धि दायक दिवस के अवसर पर श्री ज्ञान वल्लभ उपाश्रय, विवेकानंद नगर में भव्य स्नात्र पूजा संपन्न हुई। संभव संस्कार सुरभि पाठशाला के बच्चों ने पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ धार्मिक विधि संपन्न की। विशेष बात यह रही कि बच्चों ने पूरी स्नात्र पूजा बालमुमुक्षु निपुण बैद को समर्पित की। सुबह 9 बजे शुरू हुई स्नात्र पूजा में बच्चों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। भगवान की भक्ति, पूजा-विधि और धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। बच्चों ने बालमुमुक्षु निपुण बैद की संयम यात्रा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए यह विशेष पूजा समर्पित की। उपस्थित समाजजनों और श्रद्धालुओं ने बच्चों की इस भक्ति भावना की सराहना की और मुमुक्षु आत्माओं के वैराग्य भाव की अनुमोदना की। तीन दिनों तक चले संयम संग्रामोत्सव में चार मुमुक्षु आत्माओं की संयम साधना की भावना केंद्र में रही।



अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही: चिमनानी



रायपुर। जगदलपुर में स्टेट जीएसटी की सहायक आयुक्त एवं अन्य लोगों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई रंगे हाथों गिरफ्तारी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी कठोरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में सुशासन की स्थापना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिमनानी ने कहा कि जीएसटी प्रकरण में राहत देने के नाम पर रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारी और बिचौलिए के खिलाफएसीबी की यह त्वरित कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि साय सरकार में पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।

भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति चाहे कितना ही रसूखदार या किसी भी पद पर क्यों न हो, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चिमनानी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार को संरक्षण प्राप्त था और जाँच एजेंसियों के हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में स्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं।

खारून तट पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

ऐतिहासिक महादेवघाट में आज सजेगा आस्था का पुन्नी मेला

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध धार्मिक आस्था, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक ऐतिहासिक पुन्नी मेला राजधानी रायपुर के महादेव घाट में एक बार फिर अपनी भव्यता बिखेरने जा रहा है।

खारून नदी के पावन तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 24 नवंबर को श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। भगवान हटकेश्वर महादेव की नगरी में आस्था की डुबकी लगाने, दीपदान करने और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रायपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महादेव घाट स्थित प्राचीन हटकेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का संबंध कलचुरी शासनकाल से माना जाता है। प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल में हुआ था। कुछ विवरणों में इसका निर्माण वर्ष 1402 ईस्वी के आसपास बताया गया है। लोकमान्यता के अनुसार खारून नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना और कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान की परंपरा लंबे समय से प्रचलित है। समय के साथ इस धार्मिक आयोजन ने विशाल मेले का स्वरूप धारण कर लिया।



वर्तमान में शासक धर्महीन होते जा रहे हैं : यतिराजाचार्य जी महाराज

श्री दूधाधारी मठ महोत्सव के तृतीय दिवस श्रोताओं को कराया रसपान श्रीराम कथा का

रायपुर। श्री दूधाधारी मठ महोत्सव के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा के स्रोताओं को संबोधित करते हुए अनंत श्रीविभूषित श्री स्वामी यतिराजाचार्य जी महाराज अवधपुरी धाम (मूल स्थान नेपाल) ने कहा कि - वर्तमान समय में शासक धर्महीन होते जा रहे हैं। वे धर्मात्माओं को भी धर्महीन बनाना चाहते हैं समाज को ऊपर उठाकर नहीं! नीचे गिरा कर उत्थान करना चाहते हैं जो कभी संभव नहीं है उन्होंने कहा कि नारद जी के चार शिष्य थे जिनमें से दो वृद्ध हैं — वाल्मीकि और वेद् व्यास जी, तथा दो बालक ध्रुव और प्रहलाद प्रसिद्ध है। नारद जी जिसे भी मिले उन्हें उन्होंने ईश्वर का साक्षात कराया। आचार्य जी ने माँ शब्द का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि माँ का अर्थ केवल जन्म देने वाली नहीं है। मां संस्कृत का शब्द है इसका अर्थ लक्ष्मी स्वरूपा है, जो अपने स्नेह से पूरी सृष्टि को समेट लेती है। जगत जननी के लिए इस पवित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य जी ने कहा कि -रावण मानव और वानर को कुछ समझता ही नहीं था। उसे लगता था कि ये उसका कभी भी बाल बांका नहीं कर सकते! इसलिए उसने वरदान मांगा - हम काहू के मरहिं न मारें।



आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.